Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 10
अंक : 272
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
बुधवार, 08 अक्टूबर, 2025

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 महाराष्ट्रः बाढ़ प्रभावित किसानों के खातों में ...

4 बिगड़ता अनुपात और बेटियों का जीवन...

7 मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला ...

संक्षिप्त न्यूज

महागठबंधन में सीट बंटवारा तयः राजद 125 पर तो कांग्रेस को 55-57 सीटें, क्या खत्म हुई खींचतान?

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला कथित तौर पर अंतिम रूप ले चुका है। सूत्रों के अनुसार, 'महागठबंधन' आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक तौर पर सीटों के बंटवारे की घोषणा कर सकता है। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) गठबंधन में 'वरिष्ठ सहयोगी' की भूमिका निभा सकता है, जबकि कांग्रेस केवल 55-57 सीटों के साथ समझौता करती दिख रही है और पटना जिले की सभी सीटें छोड़ रही है।

प्रस्तावित सीट बंटवारे में कथित तौर पर राजद को 125 सीटें, कांग्रेस को 55 से 57 सीटें, वाम दलों को 35 सीटें, मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी को 20 सीटें, पशुपति पारस को तीन सीटें और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) को दो सीटें आवंटित की गई हैं। हालाँकि, सटीक वितरण को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच मतभेद बने हुए हैं, हालाँकि दोनों दलों के नेताओं का दावा है कि सब कुछ तय हो चुका है। कांग्रेस और राजद के बीच मुख्य विवाद कांग्रेस को आवंटित सीटों की संख्या को लेकर है। कांग्रेस कथित तौर पर 78 सीटों की मांग कर रही है, जबकि राजद नेता तेजस्वी यादव कथित तौर पर केवल 48 सीटें देने को तैयार हैं। दोनों दलों के बीच लगभग 55 सीटों पर समझौता होने की उम्मीद है।

बिहार चुनाव में कांग्रेस अपनी कुछ पारंपरिक सीटें छोड़ने को तैयार दिख रही है। उदाहरण के लिए, पटना जिले में, पार्टी ने पिछले चुनाव में चार सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार कथित तौर पर किसी पर भी दावा नहीं कर रही है। इसके अलावा, कांग्रेस के पास पहले से मौजूद कई सीटें अब राजद के खाते में जा सकती हैं। इनमें सीतामढ़ी की सुरसंड, दरभंगा की जाले और चैनपुर, और वैशाली की राजा पाकर शामिल हैं। राजा पाकर में मौजूदा कांग्रेस विधायक प्रतिमा सिंह हैं, लेकिन राजद कथित तौर पर शिवचंद्र राम को अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है।

पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौराः

नवी मुंबई एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, यूके पीएम संग होगी वैश्विक साझेदारी पर मंथन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8-9 अक्टूबर को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी दोपहर लगभग 3 बजे नवी मुंबई पहुँचेंगे और नवनिर्मित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद, लगभग 3:30 बजे, प्रधानमंत्री नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और लोकार्पण भी करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे।

9 अक्टूबर को सुबह लगभग 10 बजे, प्रधानमंत्री मुंबई में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर की मेज़बानी करेंगे। लगभग 1:40 बजे, दोनों देशों के प्रधानमंत्री मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में सीईओ फोरम में भाग लेंगे। इसके बाद, लगभग 2:45 बजे, दोनों प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण में शामिल होंगे। वे फेस्ट में मुख्य भाषण भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर 8-9

अक्टूबर 2025 को भारत आएंगे। यह प्रधानमंत्री स्टारर की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी।

इस यात्रा के दौरान, दोनों प्रधानमंत्री 'विज़न 2035' के अनुरूप भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विविध पहलुओं में प्रगति का जायजा लेंगे। यह विज़न व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों के प्रमुख स्तंभों में कार्यक्रमों और पहलों का एक केंद्रित और समयबद्ध 10-वर्षीय रोडमैप है। दोनों नेता भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) द्वारा प्रस्तुत अवसरों पर व्यवसायों और उद्योग जगत के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, जो भविष्य में भारत-ब्रिटेन आर्थिक साझेदारी के एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में कार्य करेगा। वे क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान भी करेंगे। दोनों नेता उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और नवप्रवर्तकों के साथ भी विचार-विमर्श करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टार्मर मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण में भी भाग लेंगे और इस अवसर पर मुख्य भाषण देंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 दुनिया भर के नवप्रवर्तकों, नीति निर्माताओं, केंद्रीय बैंकरों, नियामकों, निवेशकों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाएगा। सम्मेलन का मुख्य विषय, 'एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण' - एआई, संवर्धित बुद्धिमत्ता, नवाचार और समावेशन द्वारा संचालित, एक नैतिक और टिकाऊ वित्तीय भविष्य को आकार देने में प्रौद्योगिकी और मानवीय अंतर्दृष्टि के अभिसरण पर प्रकाश डालता है।

राष्ट्रपति का बड़ा बयानः

ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने LoC पार आतंकी ठिकानों को किया तबाह, दिखाई ताकत

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि देश के सशस्त्र बलों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान एकजुटता और रणनीतिक दूरदर्शिता की ताकत का प्रदर्शन किया, जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार आतंकवादी बुनियादी ढांचे को ध्वस्त किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने सात मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इलाकों में आतंकी ढांचों को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद चार दिनों तक भीषण झड़पें हुईं, जो 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति के साथ समाप्त हुईं।

यहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के 65वें पाठ्यक्रम के संकाय और पाठ्यक्रम सदस्यों को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि बदलते भू-राजनीतिक माहौल और सुरक्षा संदर्भ गतिशील प्रतिक्रियाओं की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध के लिए तैयार बल के रूप में परिवर्तित करने में लगा हुआ है, जो बहु-क्षेत्रीय एकीकृत अभियान में सक्षम हो।

राष्ट्रपति ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सशस्त्र बलों ने एकजुटता और रणनीतिक दूरदर्शिता की ताकत

का प्रदर्शन किया। सेना के तीनो अंगों की बेहतर प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप प्रभावी तालमेल स्थापित हुआ। मुर्मू ने सशस्त्र बलों के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा, नियंत्रण रेखा के पार और सीमा पार के क्षेत्रों में अंदर तक आतंकी बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने के सफल अभियान के पीछे यही तालमेल था।

राष्ट्रपति ने कहा कि एकजुटता को बढ़ावा देने की प्रक्रिया सैन्य मामलों के विभाग के गठन के साथ शुरू हुई, जिसके सचिव प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) हैं।

जीएसटी बचत उत्सव तो बस शुरुआत है, दीवाली से पहले देश को एक और बड़ा उपहार देने जा रही है मोदी सरकार

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। नवरात्रि के पावन अवसर पर मोदी सरकार ने जनता को 'जीएसटी बचत' का उपहार देकर आर्थिक मोर्चे पर एक सकारात्मक संदेश दिया है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है क्योंकि नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम के ताज़ा बयान से संकेत मिल रहे हैं कि दीवाली से पहले देश को एक और बड़ा आर्थिक तोहफा मिलने वाला है, जो भारतीय विनिर्माण और व्यापार क्षेत्र की दिशा ही बदल सकता है।

हम आपको बता दें कि सुब्रह्मण्यम ने स्पष्ट किया है कि भारत को अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए अपने विनिर्माण क्षेत्र में गहरे संरचनात्मक सुधारों की ज़रूरत है। नई राष्ट्रीय विनिर्माण नीति इसी दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकती है। उनका संकेत था कि भारत को अब टैरिफ (शुल्क) कम करने और गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने की दिशा में साहसिक फैसले लेने होंगे। इसका मतलब है कि सरकार एक ऐसी खुली नीति पर काम कर रही है, जो 'मेक इन इंडिया' को केवल नारा नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक औद्योगिक क्रांति का रूप देगी।

हम आपको बता दें कि भारत का विनिर्माण क्षेत्र अभी भी मध्यवर्ती उत्पादों की कमी से जूझ रहा है। नई नीति में क्लस्टर आधारित औद्योगिक ढांचा, विश्वस्तरीय सप्लाई चेन और निर्यातोन्मुख उत्पादन को प्राथमिकता मिलने के संकेत हैं। यह वही मॉडल है जिसने चीन, वियतनाम और दक्षिण कोरिया को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया।

मासूमों की जान लेने वाला कोल्ड्रिफ कफ सिरप बैन, पंजाब सरकार ने लिया सख्त फैसला

चड़ीगढ़। पंजाब सरकार ने मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के गंभीर दुष्प्रभावों के कारण 14 बच्चों की मौत की खबरों के बाद इसकी बिक्री, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (औषधि शाखा) ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर कहा है कि यह कफ सिरप मध्य प्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के सरकारी विश्लेषक द्वारा घोषित मानक गुणवत्ता का नहीं है।

आदेश में कहा गया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि उक्त उत्पाद का संबंध मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हाल ही में हुई बच्चों की मौतों से पाया गया है। उपर्युक्त उत्पाद को जनहित में तत्काल प्रभाव से पंजाब राज्य में बिक्री, वितरण और उपयोग के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

जातिगत जनगणना में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, कर्नाटक में स्कूल बंद कर 19 अक्टूबर तक पूरा होगा सर्वे

बैंगलुरू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कई ज़िलों में काम में देरी के चलते, चल रहे सामाजिक एवं शैक्षिक सर्वेक्षण, जिसे आमतौर पर जाति जनगणना कहा जाता है, को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। 22 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर को समाप्त होने वाला यह सर्वेक्षण अब 19 अक्टूबर तक चलेगा। सिद्धारमैया ने कहा कि कोप्पल जैसे कुछ ज़िलों ने 97 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है, जबकि दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जैसे अन्य ज़िलों ने केवल लगभग 60 प्रतिशत ही हासिल किया है। पूरे राज्य में सर्वेक्षण हमारी उम्मीदों के मुताबिक़ आगे नहीं बढ़ पाया है। इसे शुरुआती समय सीमा के भीतर पूरा करना संभव नहीं है।

शिक्षा विभाग ने स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ विचार-विमर्श के बाद सर्वेक्षण अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इस कार्य में लगभग 1.6 लाख कर्मचारी भाग ले रहे हैं, जिनमें 1.2 लाख शिक्षक और 40,000 अन्य

कर्मचारी शामिल हैं। शिक्षक संघ के अनुरोध पर, सरकार ने सर्वेक्षण कार्य को सुगम बनाने के लिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 8 से 18 अक्टूबर तक अवकाश घोषित किया है। द्वितीय पीयूसी मध्यावधि परीक्षाओं में शामिल शिक्षकों को इससे छूट दी जाएगी। बेंगलुरु में जहाँ 6,000-7,000 शिक्षक और 24,000 अन्य कर्मचारी इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, सरकार ने गणना पूरी करने के लिए नियमित सार्वजनिक अवकाशों के साथ-साथ आठ कार्य दिवसों को विशेष अवकाश के रूप में प्रदान किया है, जो कुल मिलाकर 12 दिन हैं। प्रत्येक गणनाकर्ता से प्रतिदिन 15 घरों को कवर करने की अपेक्षा की जाती है।

सिद्धारमैया ने चेतावनी दी कि सर्वेक्षण में भाग न लेने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सर्वेक्षण के दौरान मारे गए तीन लोगों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये का मुआवज़ा देने की भी घोषणा की। शिक्षकों और गणनाकारों को 20-20,000 रुपये का मानदेय, 5,000 रुपये की एक निश्चित राशि और सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक परिवार को 100 रुपये दिए जाएँगे। इस बीच, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सर्वेक्षण के साथ शैक्षणिक कार्य को संतुलित करने के लिए स्कूलों के समय में बदलाव किया है। ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र में 8 से 24 अक्टूबर तक सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक कक्षाएं चलेंगी, जबकि अन्य जिलों में 8 से 12 अक्टूबर तक समायोजित समय लागू रहेगा।

सीजेआई बीआर गवई ने सोशल मीडिया को लेकर किया आगाह

'जजों की टिप्पणी की हो रही गलत व्याख्या'

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने मंगलवार को अदालती कार्यवाही के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गईं मौखिक टिप्पणियों को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रस्तुत किए जाने पर चिंता व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश की ओर से यह बयान उन पर एक वकील द्वारा जूता उछालने की कोशिश के एक दिन बाद आया है। वकील ने खजुराहो में विष्णु की मूर्ति की पुनर्स्थापना की याचिका पर पिछले महीने मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी से नाखुश होने का दावा किया था।

सीजेआई ने सुनाया किस्सा

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश गवई ने एक किस्सा साझा किया। उन्होंने अपने सहयोगी न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन को एक मामले की पिछली सुनवाई के दौरान ऑनलाइन गलत व्याख्या से बचने के लिए कुछ खुले तौर पर टिप्पणियां करने से रोक दिया था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मेरे विद्वान भाई (न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन) को कुछ टिप्पणी करनी थी, मैंने उन्हें धीरज मोर मामले की सुनवाई के दौरान इसे व्यक्त करने से रोक दिया। वरना इसे सोशल मीडिया पर हमें नहीं पता कि क्या रिपोर्ट किया जाता? मैंने अपने विद्वान भाई से अनुरोध किया कि वे इसे केवल मेरे कानों तक ही सीमित रखें। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति चंद्रन की पीठ अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ द्वारा न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों, वेतनमान और करियर प्रगति से संबंधित मुद्दों पर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश(सीजेआई) बीआर गवई पर जूते फेंकने की कोशिश की थी। एक नाटकीय घटनाक्रम में राकेश किशोर नाम के वकील ने जूते फेंकने की असफल कोशिश की थी। जब उन्होंने डाइस की ओर बढ़ने की कोशिश की तो सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आ गए और उन्हें कोर्ट रूम से बाहर ले गए। जब वकील को ले जाया जा रहा था तो उन्हें यह कहते सुना गया, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। कथित तौर पर वह भगवान विष्णु की मूर्ति की पुनर्स्थापना पर पिछले दिनों सीजेआई की टिप्पणी से नाखुश थे। हालांकि सीजेआई ने उपस्थित वकीलों से अदालत की कार्यवाही जारी रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा, 'इस सब से विचलित न हों। हम विचलित नहीं हैं। ये बातें मुझे प्रभावित नहीं करतीं। घटना के बाद 71 वर्षीय अधिवक्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें रिहा करने के लिए कहा था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, 'वह मयूर विहार इलाके के निवासी हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के पंजीकृत सदस्य हैं।'

मराठा आरक्षणः महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर रोक लगाने की मांग, हाई कोर्ट से आया बड़ा अपडेट

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे देवेंद्र फडणवीस सरकार और मनोज जरांगे को राहत मिली है. दरअसल, आरक्षण की मांग पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2 सितंबर को जो शासन निर्णय जारी किया गया था, उसपर कई ओबीसी संगठन रोक लगाने की मांग कर रहे थे. हालांकि, कोर्ट ने अंतिम फैसला लेते हुए GR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

कोर्ट ने शासन निर्णय पर अंतरिम स्थगन देने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया है. ऐसे में मराठा आरक्षण मुद्दे पर राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है.

चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच ने यह फैसला लिया है. हैदराबाद गैजेटियर के क्रियान्वयन को मंजूरी देने वाले शासन

निर्णय के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई थीं. इन याचिकाओं के जरिए मांग की गई थी कि 2 सितंबर का शासन निर्णय असंवैधानिक है और उसे रद्द किया जाना चाहिए.

इन संस्थाओं ने दायर की थीं याचिकाएं सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए कुनबी सेना, महाराष्ट्र माली समाज महासंघ, अहीर सुवर्णकार समाज संस्था, महाराष्ट्र नाभिक महामंडल और सदानंद मंडलिक की ओर से रिट याचिकाएं दायर की गई थीं. इन संगठनों की चिंता यह है कि अगर मराठाओं को आरक्षण दिया गया तो ओबीसी के हिस्से के रिजर्वेशन कोटा पर प्रभाव पड़ेगा.

मनोज जरांगे ने सरकार के सामने यही शर्त रखी थी कि जब तक आरक्षण को लेकर जीआर जारी नहीं होता, वे आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे. इसके बाद 2 सितंबर को महाराष्ट्र कैबिनेट उप-समिति के प्रस्ताव को स्वीकार कर उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया था. देवेंद्र फडणवीस सरकार के इस फैसले से कैबिनेट में ही विरोध के स्वर उठे थे. छगन भुजबल और पंकजा मुंडे जैसे कई बड़े नेताओं ने ओबीसी आरक्षण पर गलत असर पड़ने की चिंता जताई थी.

ट्रॉम्बे पुलिस ने एक और कार्रवाई की, 1.5 लाख रुपये का 2 किलो गांजा जब्त

मुंबई।ट्रॉम्बे पुलिस ने दो दिन पहले 40,000 रुपये की 40 ग्राम ड्रग्स जब्त की थी। अब फिर से, महाराष्ट्र नगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 1.60 लाख रुपये का 2 किलो गांजा जब्त किया गया है। पिछली घटना में, पुलिस कांस्टेबल पवार, कोकरे और एमएसएफ जवान होलंबे ने इस जगह पर एक संदिग्ध वाहन देखा। उसकी जाँच करते समय, इस वाहन के चालक को उसके साथ एक बैग छिपाते हुए देखा गया, इसलिए उन्होंने बैग की जाँच की। उस बैग में 8 किलो 176 ग्राम वजन का गांजा पाया गया। इस संबंध में नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट, 1985 की धारा 8 (ए), 20 (बी), 29 के तहत ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और राहुल पिंटू शिंदे (पलावा सिटी के पास शिलफाटा) से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गांजा, एक वैगनर मोटर कार, मोबाइल फोन और 3,000 रुपये की नकदी सहित संपत्ति जब्त की। इस बीच, इस अपराध में आगे की जांच के

दौरान पता चला कि गिरफ्तार आरोपी के कुछ और साथी भी थे और वे ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन की सीमा में बिक्री के लिए मादक पदार्थ गांजा ला रहे थे। तदनुसार, ट्रॉम्बे पुलिस ने फरार आरोपी राजू अंबादास शिंदे की तलाश के लिए एक टीम बनाई। इस टीम ने तकनीकी जांच करने के बाद कल्याण से उसका पीछा किया। आरोपी वाशी टोल प्लाजा के पास साउथ चैनल मुंबई की ओर जाने वाली सड़क पर पाया गया। इस आरोपी के कब्जे से 40,000 रुपये मूल्य के 2 किलो 50 ग्राम गांजा के साथ एक 4-पहिया वाहन मिला। उन्होंने बताया है कि वह इस मादक पदार्थ को चिता कैंप, महाराष्ट्र नगर, मानखुर्द क्षेत्र में बिक्री के लिए लाया था। इस बीच, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ धाराशिव में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत बिक्री के लिए रखने का मामला दर्ज किया गया है। अब अधिकारी सुशील लोंढे इस अपराध की आगे की जाँच कर रहे हैं।

यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त देवेन भारती, सह पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी, अपर पुलिस आयुक्त महेश पाटिल, परिमंडल 6 पुलिस उपायुक्त समीर शेख, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ऋता नेमलेकर के मार्गदर्शन में किया गया है।

जांच अभियानों से प्राप्त किया 97 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना

पश्चिम रेलवे ने अप्रैल से सितम्बर, 2025 के दौरान गहन टिकट

एसी उपनगरीय लोकल से प्राप्त किया गया 1.59 करोड़ रुपये का जुर्माना

मुंबई(संवाददाता)।पश्चिम रेलवे द्वारा सभी वैध यात्रियों को सुगम, आरामदायक यात्रा और बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए मुंबई उपनगरीय लोकल ट्रेनों, मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों, पैसेंजर ट्रेनों तथा हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों में बिना टिकट/अनियमित यात्रियों पर अंकुश लगाने हेतु निरंतर गहन टिकट जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारियों की देखरेख में टिकट जांच दलों द्वारा अप्रैल से सितम्बर, 2025 की अवधि में विविध टिकट जांच अभियानों के माध्यम से कुल 97.47 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की गई, जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 42इ से अधिक है, साथ ही रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य से लगभग 15इ अधिक है। इस राशि में मुंबई उपनगरीय खंड से 27 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सितम्बर,

2025 के दौरान बिना टिकट/अनियमित यात्रा तथा बिना बुक किए गए सामान से जुड़े 2.35 लाख मामलों का पता लगाकर 13.28 करोड़ रुपये की वसूली की गई, जो पिछले वर्ष के सितम्बर के आंकड़ों की तुलना में 116इ से अधिक है। साथ ही, मुंबई उपनगरीय खंड पर 96 हजार मामलों का पता लगाकर 4 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना प्राप्त किया गया है। एसी लोकल ट्रेनों में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए लगातार औचक टिकट जांच अभियान भी चलाए जा रहे हैं। एसी लोकल में केंद्रित अभियानों के परिणामस्वरूप, अप्रैल से सितम्बर 2025 के दौरान लगभग 49 हजार अनधिकृत यात्रियों को दंडित किया गया और उनसे 1.59 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में प्राप्त किए गए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 70इ अधिक है। ऐसे उल्लेखनीय परिणाम अनधिकृत यात्रा पर अंकुश लगाने, यात्री अनुभव को बेहतर बनाने और सार्वजनिक राजस्व की सुरक्षा के लिए पश्चिम रेलवे की प्रतिबद्धता के प्रमाण हैं।

पश्चिम रेलवे आम जनता से अपील करता है कि कृपया उचित और वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें।

पश्चिम रेलवे द्वारा लिफ्टों, एस्केलेटरों और अर्थिंग पिट्स के लिए स्मार्ट डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम 'सुगम रेल' लॉन्च

रजिस्टरों को रियल टाइम की जानकारी में बदलना, पश्चिम रेलवे द्वारा स्मार्ट मॉनिटरिंग में बेंचमार्क स्थापित

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सुगम रेल डिजिटल मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करते हुए।

पश्चिम रेलवे ने डिजिटल गवर्नेंस तथा यात्री सुरक्षा के क्षेत्र में एक और उपलब्धि अर्जित की है। सुगम रेल भारतीय रेल पर अपनी तरह का पहला सॉफ्टवेयर आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे लिफ्टों, एस्केलेटरों और अर्थिंग पिट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए डिजाइन किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह एप्लिकेशन पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य मुख्य सुरक्षा और रखरखाव प्रणालियों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना है। इससे पहले लिफ्टों, एस्केलेटरों और अर्थिंग अवसंरचना का पर्यवेक्षण कई डिपो में बनाए गए मैनुअल रजिस्टरों

पर निर्भर था, जिसके कारण खराबी का पता लगाने में देरी, फ्रेगमेंटेड रिपोर्टिंग और सीमित जवाबदेही होती थी। सुगम रेल के कार्यान्वयन के साथ पश्चिम रेलवे में 470 से अधिक लिफ्ट/एस्केलेटर और लगभग 21,500 अर्थिंग पिट अब एक एकीकृत डिजिटल डैशबोर्ड के अंतर्गत आ गए हैं, जो मंडल और मुख्यालय स्तर पर अधिकारियों के लिए सुलभ है। यह प्रणाली उपकरणों की स्थिति की चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित करती है, बार-बार होने वाली खराबी या अतिदेय निरीक्षणों को स्वचालित रूप से चिह्नित करती है और उच्च अनुपालन के साथ समय पर हस्तक्षेप को सक्षम बनाती है। यह परिसंपत्ति-वार और कारण-वार विस्तृत विफलता विश्लेषण प्रदान करती है, जबकि विफलताओं के बीच औसत समय (एमटीबीएफ) और रखरखाव अनुपालन दर जैसे प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) का उपयोग परिसंपत्ति विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए किया जाता है।

अपने परिचालन लाभों के अलावा, यह पहल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। लिफ्ट और एस्केलेटर के प्रदर्शन की डिजिटल ट्रैकिंग, ब्रेकडाउन पर तेज़ी से ध्यान देने में मदद करती है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन यात्रियों और बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं को लाभ होता है। साथ ही, अर्थिंग प्रतिरोध की संरचित निगरानी विद्युत खतरों को रोकने में मदद करती है और स्टेशनों और रेलवे प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करती है। भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल, एनालिटिक्स-समर्थित तंत्र से बदलकर, पश्चिम रेलवे ने रेलवे अवसंरचना प्रबंधन में एक नया मानदंड स्थापित किया है। सुगम रेल के चालू होने के साथ पश्चिम रेलवे ने सुरक्षित, स्मार्ट और जवाबदेह रेल संचालन के लिए बुद्धिमान डिजिटल समाधानों को अपनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है। यह प्लेटफ़ॉर्म सार्वजनिक सेवा वितरण में उभरती माँगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए नवपरिर्तन के एक मॉडल के रूप में खड़ा है।

'स्वच्छ रेलगाड़ी, प्रसन्न यात्री', पिट लाइन से लेकर कोच तकः स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के दौरान मध्य रेल का सोलापुर मंडल गतिमान

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल के सोलापुर मंडल ने 5 और 6 अक्टूबर को 'स्वच्छ रेलगाड़ी' (स्वच्छ ट्रेन) थीम के तहत अपने समर्पित प्रयासों को जारी रखा, जिसमें चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत ट्रेनों में और रखरखाव डिपो पर स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

5वां दिन - 5 अक्टूबर स्वच्छ ट्रेन निरीक्षण और ओबीएचएस परामर्श

पांचवें दिन, मंडल भर में विभिन्न स्थानों पर वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियरों (एसएसई) और मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकों (सीएचआई) द्वारा ट्रेनों का गहन निरीक्षण किया गया। ट्रेने शामिल हैं:

पंढरपुर-मैसूर एक्सप्रेस, पंढरपुर में, लातूर-यशवंतपुर एक्सप्रेस, लातूर में, हरंगुल-पुणे एक्सप्रेस, हरंगुल में, लातूर-एलटीटी मुंबई एक्सप्रेस, लातूर में। ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग सेवाओं (ओबीएचएस) के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सफाई और रखरखाव के लिए सामग्री की उपलब्धता की भी जाँच की गई। ओबीएचएस कर्मचारियों को सेवा मानकों को बेहतर

बनाने और यात्रियों की शिकायतों को कम करने के लिए परामर्श दिया गया। इसके अतिरिक्त, मुख्य रूप से रखरखाव किए गए रेकों की जाँच की गई ताकि डिब्बों के अंदर सफाई और कूड़ा-कचरा न फैलाने संबंधी पोस्टरों का उचित प्रदर्शन किया जा सके। यात्रियों में जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर चिपकाए गए।

छठे दिन, सोलापुर में आधुनिक उपकरणों और मशीनीकृत उपकरणों का उपयोग करके ट्रेनों की पिट लाइनों पर गहन सफाई की गई। सफाई का निरीक्षण एसएसई द्वारा किया गया। इनमें शामिल ट्रेनें हैं: सिद्धेश्वर एक्सप्रेस, हसन एक्सप्रेस, हुतात्मा एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस।

संतुष्टि स्तर का आकलन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए ओबीएचएस कर्मचारियों द्वारा यात्रियों से फीडबैक फॉर्म एकत्र किए गए। सभी डिब्बों में स्वच्छता जागरूकता पोस्टरों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रेकों की फिर से गहन जाँच की गई।

सोलापुर मंडल, ट्रेनों में और रखरखाव क्षेत्रों में स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए स्वच्छता पखवाड़ा की भावना को कायम रखता है। मंडल यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही स्वच्छता और ज़िम्मेदार यात्रा आदतों के महत्व के बारे में जागरूकता भी बढ़ाता है।

घाटकोपर पुलिस ने ड्रग डीलरों पर शिकंजा कसना शुरू किया, ड्रग्स के साथ दो गिरफ्तार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। पिछले कुछ वर्षों से घाटकोपर पूर्व और पश्चिम में ड्रग डीलर उत्पात मचा रहे हैं। नागरिक इस संबंध में पुलिस से बार-बार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालाँकि, कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण, ड्रग डीलरों को खुली छूट मिल रही है। हालाँकि, अब घाटकोपर पश्चिम के नागरिकों, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा एक बयान दर्ज करके पुलिस पर दबाव बनाने के बाद, आज सुबह दो लोगों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी सोहेल हारुन खान और उसके एक साथी के खिलाफ अब एनडीपीएस एक्ट और धारा 8 (सी) के साथ धारा 22 (1985) के तहत मामला दर्ज किया गया है।घाटकोपर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सतीश जाधव ने बताया कि अब से पुलिस की कार्रवाई तेज होगी। पुलिस ने नित्यानंद नगर इलाके में चाइना टाउन होटल के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 50,000 रुपये मूल्य की 5 ग्राम एमडी जब्त की। उसके पास से एक मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है और यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि उसका संबंध किससे है। सोमवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने पुलिस को एक बयान सौंपकर घाटकोपर पश्चिम में स्कूली छात्रों को ड्रग्स खरीदने और बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। राजेश सावंत, नंदा गव्हाणे, पूर्व नगरसेवक अश्विनी मते, पूर्व नगरसेवक दीपक बाबा हांडे, सूर्यकांत गवली, उमाकांत चव्हाण, प्रकाश पाटिल, दत्तात्रय चौगुले, प्रकाश तावड़े, विजय बाबर, संतोष सानलुखे, अमोल मतेले, कोकांति, प्रतीक थोरांट संदीप सावंत और सभी सामाजिक और राजनीतिक दलों के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

इस बीच, रविवार को घाटकोपर में 'मोकला श्वास फाउंडेशन' द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोगों की एक बैठक आयोजित की गई है। संगठन के अध्यक्ष राजेश सावंत ने बताया कि उनके संबंधित विभागों में पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस कड़ी नजर रखेगी.... सतीश जाधव, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, घाटकोपर पुलिस स्टेशन। मामले की आगे जांच उपनिरीक्षक सत्यवान शिंगारे कर रहे है।

मध्य रेल

सोलापुर मण्डल

इंजीनियरिंग कार्य

मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) सोलापुर, भारत के राष्ट्रपति के लिये और उनकी और से निम्नलिखित कार्यों के लिये ई–निविदये आमंत्रित करते है। निविदा क्र.:–13-2025-SrDENCo कार्य का नाम :– **i) Proposed coaching maintenance depot at TKWD (Phase-I) ii) Creation of trip maintenance / advance inspection centers for inspection and maintenance activity of electric locomotives at TKWD.** अनुमानित लागत :– रू. **38,30,55,085.48/-** बयाना रक्कम :– रू **20,65,300.00/-** समापन की अवधी :– 12 Months अनुरक्षण की अवधी :– 12 Months **www.ireps.gov.in** इस वेब साईट पर टेंडर अपलोड करणे कि अंतिम दिनांक और समय : **13-2025-SrDENCo - 24/10/2025** को **15:00** बजे तक **www.ireps.gov.in** इस वेब साईट पर टेंडर खुलने का दिनांक और समय : **13-2025-SrDENCo - 24/10/2025** को **15:30** बजे। निविदाकारों से निवेदन हैं की कोई बदलाव/शुद्धिपत्र (यदि हो) के लिये website **www.ireps.gov.in.** पर टेंडर बंद होने की तारीख तक समय समय पर भेंट दे। ANJ-59

अपने जानवरों को रेल लाइन से दूर रखे

मुंबई में बार की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, 8 महिलाएं रेस्क्यू

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई के चेंबूर इलाके में बार और रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे एक सेक्स रैकेट का मुंबई पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. आरसीएफ (ंएड) और तिलक नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में प्रमिला बार एंड रेस्टोरेंट से बार मालिक, मैनेजर और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मौके से 8 महिलाओं को रेस्क्यू भी किया है।

पुलिस को आरसीएफ थाने के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि चेंबूर के आरसी मार्ग स्थित प्रमिला बार एंड रेस्टोरेंट में वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है. जानकारी की पुष्टि के लिए आरसीएफ और तिलक नगर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया. योजना के तहत पुलिस ने एक फर्जी ग्राहक को

बार में भेजा ताकि सच सामने आ सके। फर्जी ग्राहक ने बार मैनेजर निशिकांत सदानंद साहू से संपर्क किया. बातचीत के दौरान मैनेजर ने बताया कि यौन सेवाओं का शुल्क 1,000 रुपये होगा. ग्राहक ने हामी भरी और उसे बार की पहली मंजिल पर ले जाया गया. वहां उसने ड्रिंक का ऑर्डर दिया. कुछ देर बाद एक महिला बारटेंडर उसके पास आई और अनुचित व्यवहार करने लगी। इसी दौरान पुलिस की टीम ने तुरंत बार में छापा मारा और पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया. अंबेडकर नगर, मानखुर्द निवासी 41 वर्षीय महिला को फर्जी ग्राहक से रुपये लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया. पुलिस ने वह रकम सबूत के तौर पर जब्त कर ली।

छापे के दौरान बार में कुल 8 महिलाएं पाई गईं जो कथित रूप से इस अवैध गतिविधि में शामिल थीं. ये महिलाएं चेंबूर, तिलक नगर, मानखुर्द और उल्हासनगर जैसे अलग-अलग इलाकों की रहने वाली हैं. पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि उनके मोहल्ले में पहले से इस काम में लिप्त कुछ लोगों ने उन्हें इसमें धकेला।

पूछताछ के दौरान बार मैनेजर निशिकांत साहू ने स्वीकार किया कि वह बार मालिक वसंत चंद्रशेखर शेट्टी के साथ मिलकर सेक्स रैकेट चला रहा था. दोनों ने महिलाओं से संपर्क साधने और ग्राहकों से पैसे लेकर उन्हें भेजने की बात कबूल की। पुलिस ने इस मामले में बार मालिक वसंत शेट्टी, मैनेजर निशिकांत साहू और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया है। सभी पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पश्चिम रेलवे

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य - प्रबंधक, मुंबई सेंट्रल मंडल, पश्चिम रेलवे
मंडल रेल प्रबंधक, वाणिज्य विभाग, एनएफआर अनुभाग, मुंबई सेंट्रल, मुंबई - 400 008।

कार्य - मुंबई मंडल में विभिन्न एनएफआर मीडिया के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करना।

नीलामी सूची क्रमांक	नीलामी प्रारंभ (सभी लॉट)
MMCT-ADVT-25-43	22-10-25 15:00:00

अ. क्र.	लॉट संख्या	स्थान/क्षेत्र	दिन	ई-नीलामी की समाप्ति तिथि और समय
1	**ADVT-BCT-NSP-OH-351-25-2** (Advertising - Out of Home)	नालासोपारा ((बुकिंग कार्यालय के कतार क्षेत्र से सटे उत्तर पूर्व परिसंचारी क्षेत्र में 20' X 10' आकार के 03 होर्डिंग्स)) में 600 वर्ग फीट के कुल क्षेत्रफल में नए होर्डिंग ढांचे के निर्माण द्वारा विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए 07 वर्षों की अवधि के लिए थोक विज्ञापन अधिकार।	2557	22-10-25 15:30:00
2	**ADVT-BCT-BVI-OH-365-25-2** (Advertising - Out of Home)	बोरीवली स्टेशन पश्चिम में एसएसई (पी.वे)-बीवीआई के परिसर में, पश्चिम की ओर मुख करके और गांजावाला लेन से आने वाले यातायात के लिए 20' x 20' (1) = 400 वर्ग फुट आकार के नए होर्डिंग ढांचे के निर्माण द्वारा विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए 07 वर्षों की अवधि के लिए थोक विज्ञापन अधिकार।	2557	22-10-25 15:40:00
3	**ADVT-BCT-ST-OSN-434-25-2** (Advertising - On Station Premise (Non-Digital))	सूरत (एसटी) स्टेशन पर तीन वर्ष की अवधि के लिए थोक विज्ञापन अधिकार।	1096	22-10-25 15:50:00
4	**ADVT-BCT-NVS-OSN-444-25-1** (Advertising - On Station Premise (Non-Digital))	नवसारी (एनवीएस) स्टेशन पर तीन वर्ष की अवधि के लिए थोक विज्ञापन अधिकार।	1096	22-10-25 16:00:00

संपर्क विवरणः लैंडलाइन नंबरः 02267644212. **ईमेल आईडीः** acmadvtgbct@gmail.com **नोटः** संभावित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे IREPS वेबसाइट (www.ireps.gov.in) पर ई-नीलामी लीजिंग मॉड्यूल देखें। लॉट-वार विवरण नीचे दिए गए कैटलॉग में उपलब्ध हैं। 0678

Like us on: facebook.com/WesternRly • Follow us on: X.com/WesternRly

महाराष्ट्रः बाढ़ प्रभावित किसानों के खातों में सीधे आएंगे 31,628 करोड़, अब तक का सबसे बड़ा पैकेज

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को हाल ही में आई बाढ़ और भारी बारिश से भारी नुकसान झेलने वाले किसानों की सहायता के लिए 31,628 करोड़ रुपये के व्यापक राहत पैकेज की घोषणा की। उपमुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, फडणवीस ने कहा कि सरकार बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि के लिए 47,000 रुपये नकद और रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के माध्यम से प्रति हेक्टेयर 3 लाख रुपये प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रभावित किसान को 10,000 रुपये नकद राहत और प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुएं के लिए 30,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुधन के नुकसान को भी कवर किया जाएगा, प्रत्येक मृत पशु के लिए 32,000 रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा - एनडीआरएफ के पहले के मानदंड का विस्तार करते हुए, जिसमें सहायता केवल तीन पशुओं तक सीमित

थी। फडणवीस ने आगे कहा कि क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए घरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी, साथ ही नुकसान उठाने वाले दुकानदारों को 50,000 रुपये की राहत भी दी जाएगी। फडणवीस ने बताया कि बाढ़ ने राज्य के 36 जिलों में से 29 को प्रभावित किया है, जिनमें 253 तालुका और 2,000 से ज़्यादा राजस्व मंडल शामिल हैं। मानसून के दौरान बोई गई 1.43 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन में से 68 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा फ़सलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। उन्होंने बताया कि कटाव के कारण लगभग 60,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की ऊपरी मिट्टी नष्ट हो गई है, जिससे पुनर्निर्माण की चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं।

राहत पैकेज में फसलों, ज़मीन, घरों, मवेशियों के बाड़ों और सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे को हुए नुकसान की भरपाई शामिल होगी। इसमें घायलों के इलाज के लिए मुआवज़ा और शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह राशि भी शामिल होगी। फडणवीस ने कहा, 'किसानों को होने वाले आर्थिक और भावनात्मक आघात के लिए कोई भी 100 प्रतिशत मुआवज़ा नहीं दे सकता, लेकिन हमारा उद्देश्य उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि किसान आगामी रबी सीज़न के लिए तैयार रहें। मुआवज़ा राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त, लगभग 45 लाख बीमित किसानों को फसल बीमा भुगतान के माध्यम से प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपये मिलेंगे।

लवणीय और आर्द्रभूमि भूमि के सुधार हेतु संशोधित मानदंड बनाए जाएं- मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल ने निर्देश दिया है कि राज्य में लवणीय और आर्द्रभूमि भूमि के सुधार हेतु नए और प्रभावी उपायों को लागू करने की आवश्यकता है और इसके लिए संशोधित मानदंड तैयार किए जाएँ।

जल संसाधन मंत्री विखे-पाटिल की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे, विधायक राजेंद्र पाटिल-यादावकर, विधायक राहुल कुल, विधायक सत्यजीत देशमुख, जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसारे, कृष्णा बेसिन विकास निगम के कार्यकारी निदेशक श्री गुनाले और जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जल संसाधन मंत्री विखे-पाटिल ने कहा कि राज्य में लवणीय और आर्द्रभूमि भूमि की समस्या का कृषि उत्पादन क्षमता पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। किसानों की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए खुली चराई योजनाएँ और भूमिगत चराई योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के वर्तमान मापदंडों को वास्तविक स्थिति के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है। इससे इन योजनाओं की दक्षता बढ़ेगी और किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। चूँकि इन योजनाओं के पूरा होने के बाद इनका नियमित रखरखाव और मरम्मत भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है, जल संसाधन मंत्री विखे-पाटिल ने कहा।

इस बैठक के बाद, सोलापुर जिला कलेक्टर कुमार आशीर्वाद ने सोलापुर जल पर्यटन परियोजना के संबंध में एक प्रस्तुति दी।

राज्य रत्न एवं आभूषण नीति - 2025 की घोषणा, राज्य में निवेश को बढ़ावा, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा

1 लाख करोड़ रुपये का निवेश, 5 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र रत्न एवं आभूषण नीति 2025, जिसका उद्देश्य 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और 5 लाख नए रोजगार सृजित करना है, को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। इस नीति का उद्देश्य इस क्षेत्र से निर्यात को 15 अरब डॉलर से बढ़ाकर 30 अरब डॉलर करना है। महाराष्ट्र रत्न एवं आभूषण नीति 2025 से 2030 तक की अवधि के लिए लागू रहेगी। नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहन के रूप में 1,651 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। अगले 20 वर्षों, यानी 2031 से 2050 तक, कुल 13,835 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी गई है, जिसमें 12,184 करोड़ रुपये शामिल हैं। वर्ष 2025-26 के लिए नीति के कार्यान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य उन्नत तकनीक अपनाकर महाराष्ट्र को वैश्विक स्तर पर रत्न एवं आभूषण उद्योग के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है। रत्न एवं आभूषण नीति एक व्यापक नीतिगत ढाँचे पर आधारित है। इसका उद्देश्य बुनियादी ढाँचे के विकास, नवाचार और कौशल विकास के माध्यम से इस क्षेत्र को मज़बूत बनाना है। इसका उद्देश्य औद्योगिक समूहों को बढ़ावा देकर, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करके और डिजिटल व्यापार समाधानों को एकीकृत करके महाराष्ट्र को रत्न एवं आभूषणों के उत्पादन और निर्यात में वैश्विक अग्रणी बनाना है। इस नीति के अंतर्गत आने वाली उद्योग इकाइयों को रियायतों और प्रोत्साहनों के अनुसार वित्तीय और अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। इसमें ब्याज सब्सिडी, निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन, स्टांप शुल्क में छूट, बिजली दरों और टैरिफ में छूट, समूह विकास, कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान, कौशल विकास सहायता, निर्यात के लिए आवश्यक सुविधाएँ और प्रोत्साहन, ब्रांडिंग-डिज़ाइनिंग-पैकेजिंग-मार्केटिंग के लिए प्रोत्साहन, वन-विंडो योजना, प्लग एंड प्ले सुविधाएँ, निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति, और अतिरिक्त मैट इंडेक्स शामिल होंगे। रत्न और आभूषण क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है। राज्य में व्यापार, डिज़ाइन, प्रौद्योगिकी और मूल्यवर्धित निर्यात में अपार अवसर हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी जैसी तकनीक में तेज़ी से हो रहे बदलावों और बुनियादी ढाँचे और कौशल के विकास की आवश्यकता के कारण बुनियादी ढाँचे और कौशल के विकास की आवश्यकता महसूस की गई।

मुंबई पुलिस के सवालों के घेरे में शिल्पा शेट्टी! 60 करोड़ के फ्रॉड मामले में ईओडब्ल्यू ने दर्ज किए बयान

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई । मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कथित तौर पर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया है। यह मामला उनके पति और व्यवसायी राज कुंद्रा से जुड़ा है। खबरों के मुताबिक, ईओडब्ल्यू ने शिल्पा से उनके आवास पर करीब 4-5 घंटे पूछताछ की और उनकी विज्ञापन कंपनी के बैंक खाते से जुड़े लेन-देन की विस्तृत जानकारी मांगी। इस दौरान उन्होंने कई अहम दस्तावेज जमा किए, जिनकी अब जांच की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस कंपनी की भूमिका की जांच कर रही है तथा चल रही जांच के तहत सम्पूर्ण वित्तीय लेनदेन रिकॉर्ड की समीक्षा कर रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को थाईलैंड के फुकेत में पारिवारिक अवकाश के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। दंपति ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर को निलंबित करने का अनुरोध किया था, यह तर्क देते हुए कि उन्होंने 2 से 5 अक्टूबर के बीच यात्रा के लिए बुकिंग की पुष्टि कर दी थी। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ पहले

ही गंभीर आर्थिक अपराध दर्ज किए जा चुके हैं और दो मामले अभी भी लंबित हैं। इसलिए, उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देना उचित नहीं होगा। शिल्पा और राज ने कहा कि यह मामला कई साल पुराना है और राज कुंद्रा ने हमेशा जांच में सहयोग किया है। उन्होंने समन मिलने पर पुलिस पूछताछ में भी हिस्सा लिया है। शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जांच के घेरे में हैं। मुंबई के व्यवसायी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर कंपनी से 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कोठारी लोटस कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज नामक एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के निदेशक हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, वह राजेश आर्य नामक व्यक्ति के माध्यम से कुंद्रा और उनकी अभिनेत्री पत्नी के संपर्क में आए। कुंद्रा और शेट्टी होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। आर्या के माध्यम से, उन्होंने 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा, लेकिन उच्च कराधान से बचने के लिए, उन्होंने इसे निवेश के रूप में दिखाया।

एसआरए के अंतर्गत झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास हेतु एक समूह पुनर्विकास योजना लागू की जाएगी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई क्षेत्र में बड़ी निजी, सरकारी और अर्ध-सरकारी भूमि पर स्थित झुग्गी बस्तियों के विकास हेतु बृहन्मुंबई झुग्गी बस्ती पुनर्वास प्राधिकरण के माध्यम से झुग्गी बस्ती क्लस्टर पुनर्विकास योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।

मुंबई में झुग्गी बस्तियों के साथ-साथ कुछ पुरानी जीर्ण-शीर्ण इमारतें, ढाँचे, किरायेदारों द्वारा अधिगृहीत इमारतें, निर्माण के लिए अनुपयुक्त खाली भूमि और कुछ बस्तियाँ भी हैं। शहरी नियोजन के दृष्टिकोण से ऐसे क्षेत्रों का एकीकृत और टिकाऊ तरीके से पुनर्विकास करने के लिए यह क्लस्टर पुनर्विकास योजना लागू की जा रही है। ताकि सभी नागरिक सुविधाओं का भी आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से विकास किया जा सके, जिससे यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। इसके लिए एक विशेष क्लस्टर पुनर्विकास योजना तैयार की गई है। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार, झुग्गी बस्ती पुनर्वास प्राधिकरण, झुग्गी बस्ती क्लस्टर पुनर्विकास योजना के लिए नोडल एजेंसी होगी।

झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण न्यूनतम 50 एकड़ के सन्निहित क्षेत्रफल वाले भूमि के एक समूह की पहचान करेगा, जिसमें 51 प्रतिशत से अधिक झुग्गी क्षेत्र शामिल होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण, ग्रेटर मुंबई द्वारा पहचाने गए समूह क्षेत्र को अतिरिक्त मुख्य सचिव, आवास की अध्यक्षता में गठित एक उच्च-स्तरीय समिति और तत्पश्चात सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

यह पुनर्विकास योजना किसी संयुक्त उद्यम के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु किसी सरकारी एजेंसी को दी जानी चाहिए या किसी निजी डेवलपर को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाना चाहिए या यदि किसी डेवलपर के पास ऐसी समूह पुनर्विकास योजना के कुल क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल है, तो समूह पुनर्विकास योजना को डेवलपर के माध्यम से क्रियान्वित करने का निर्णय उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार की पूर्व अनुमति से लिया जाएगा।

केंद्र सरकार और उसके अधीनस्थ उपक्रमों की भूमि के मामले में, यदि केंद्र सरकार/संबंधित उपक्रम अपनी सहमति देते हैं, तो यह भूमि झुग्गी क्लस्टर पुनर्विकास योजना में शामिल की जाएगी।

यदि स्लम क्लस्टर पुनर्विकास योजना में कुछ भवन विकास नियंत्रण एवं संवर्धन नियम, 2034 के विनियम 33(10) के अतिरिक्त अन्य प्रावधानों (जैसे 33(7), 33(5), 33(9) या अन्य) के अंतर्गत विकास हेतु पात्र हैं, तो ऐसे भवनों को क्लस्टर पुनर्विकास में शामिल करने पर उन्हें धारा 33(10) के अंतर्गत प्रदत्त लाभ या संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध लाभ, जो भी अधिक हो, दिया जाएगा।

निजी भूमि के स्वामियों को, यदि संभव हो तो, उच्च स्तरीय समिति के पूर्व अनुमोदन से, प्रस्तावित स्लम क्लस्टर पुनर्विकास योजना में शामिल करने के लिए, नगर नियोजन योजना की तर्ज पर मूल्यांकित समतुल्य फ्लोर एरिया इंडेक्स वाला एक विकसित भूखंड प्रदान किया जाएगा। यदि निजी भूमि स्वामी ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं, तो ऐसी भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 के अनुसार किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण की लागत परियोजना को क्रियान्वित करने वाले प्रमोटर/डेवलपर द्वारा वहन की जाएगी।

तटीय विनियमन क्षेत्र-I और क्षेत्र-II से प्रभावित क्षेत्रों में यदि मलिन बस्तियाँ हैं, तो ऐसी मलिन बस्तियों को मलिन बस्ती क्लस्टर पुनर्विकास योजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही, उनमें स्थित मलिन बस्तियों का पुनर्वास मलिन बस्ती क्लस्टर पुनर्विकास योजना के किसी भी भाग में किया जाएगा।

ज़ोन-1 से ऊपर की झोपड़ियों के पुनर्वास से खाली हुई भूमि पर नियमानुसार सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। साथ ही, विकासकर्ता ज़ोन-2 से ऊपर की झोपड़ियों के पुनर्वास से खाली हुई भूमि पर नियमानुसार खुदरा इकाई का निर्माण कर सकेगा।

किसी मलिन बस्ती क्लस्टर पुनर्विकास योजना में, यदि पुनर्वास से अधिक निर्माण व्यावहारिक रूप से संभव हो, तो 4 मटई क्षेत्र सूचकांक की सीमा से अधिक निर्माण की अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, ऐसे निर्माण का उपयोग केवल क्लस्टर पुनर्विकास योजना के बाहर की भूमि पर विकास के लिए अनुपयुक्त मलिन बस्तियों को हटाने या परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के पुनर्वास के लिए किया जाएगा। ऐसे निर्माण के लिए विकास नियंत्रण नियम, 2034 के विनियम 33(10) के अंतर्गत प्रोत्साहन लाभ प्रदान किए जाएँगे।

बाढ़ की स्थिति के कारण त्रिभाषी नीति समिति का छत्रपति संभाजीनगर दौरा स्थगित

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई।राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य के स्कूलों में त्रिभाषी नीति सुनिश्चित करने के लिए डॉ. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद के उप निदेशक (परियोजना/प्रशासन) संजय दोरलीकर ने बताया कि समिति का 8 अक्टूबर को छत्रपति संभाजीनगर दौरा स्थगित कर दिया गया है।

17 सितंबर, 2025 को त्रिभाषी नीति समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समिति के सदस्य राज्य के आठ स्थानों का दौरा करेंगे और राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं, शिक्षाविदों, संस्थाओं के प्रतिनिधियों, अभिभावक-शिक्षक संघों के पदाधिकारियों, बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं के विचार जानेंगे। तदनुसार, बैठक में 8 अक्टूबर, 2025 को छत्रपति संभाजीनगर का दौरा करने का निर्णय लिया गया।

पिछले कुछ दिनों से मराठवाड़ा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण मराठवाड़ा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्षेत्रीय स्तर पर सभी व्यवस्थाएँ नागरिकों को राहत पहुँचाने में जुटी हुई हैं। बाढ़ की स्थिति अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। ऐसे में समिति का 8 अक्टूबर का छत्रपति संभाजीनगर दौरा स्थगित कर दिया गया है। छत्रपति संभाजीनगर दौरे की तिथि जल्द से जल्द घोषित की जाएगी। शेष स्थानों अर्थात नागपुर, कोल्हापुर, रत्नागिरी, नासिक, पुणे, सोलापुर और मुंबई का दौरा पूर्व घोषित तिथियों के अनुसार किया जाएगा।

रोहिणी खडसे से पुणे पुलिस ने की पूछताछ, पति प्रांजल खेवलकर हैं आरोपी

पुणे (एजेंसी)। पुणे शहर पुलिस ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा-सपा) की नेता रोहिणी खडसे का बयान उनके पति डॉ. प्रांजल खेवलकर के खिलाफ कथित ड्रग्स पार्टी मामले में दर्ज किया।

बाद में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, रोहिणी ने कहा कि पुलिस ने उन्हें मामले से जुड़े कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा कि मैंने मुझसे पूछे गए सवालों के जवाब दे दिए हैं... मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए मीडिया के साथ विवरण साझा करना उचित नहीं होगा। हम पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं। रोहिणी ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि उनके पति निर्दोष हैं और यह बात अदालत में साबित हो जाएगी। रोहिणी वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे की बेटी हैं।

रोहिणी सोमवार सुबह पुणे पुलिस कमिश्नरेट स्थित क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुँचीं। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। पुलिस ने 25 जुलाई को तड़के करीब 3.20 बजे खराडी स्थित स्टेबर्ड एज़्योर सुइट बिल्डिंग के अपार्टमेंट नंबर 102 में छापेमारी के दौरान खेवलकर को चार पुरुषों और दो महिलाओं के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि मौके से 2.7 ग्राम कोकीन, 70 ग्राम मारिजुआना और दस मोबाइल फोन, दो कारें, एक हुक्का पॉट, शराब और बीयर की बोतलें समेत अन्य सामान जब्त किया गया, जिनकी कीमत 41,35,400 रुपये है। फोरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि खेवलकर ने कोई ड्रग्स नहीं लिया था। इस मामले में 25 सितंबर को एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।

खेवलकर ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में दलील दी थी कि पुलिस ने इस मामले में ज़ब्त की गई प्रतिबंधित सामग्री 'राजनीतिक' कारणों से रखी थी। वकील ने तर्क दिया था कि खेवलकर ने न तो ड्रग्स का सेवन किया था और न ही उनके पास से कोई ड्रग्स बरामद हुई थी, इसलिए उनके खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत लगाए गए आरोप झूठे हैं।

विभाग के आश्रम विद्यालयों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित प्रगति योजना

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

विजभज वर्ग के निजी सहायता प्राप्त आवासीय प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, गन्ना श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियों के लिए आवासीय आश्रम विद्यालयों और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यानिकेतन आश्रम विद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए दो लाभों सहित संशोधित सेवाकालीन सुनिश्चित प्रगति योजना लागू करने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।

संशोधित सेवाकालीन आश्वासन योजना पहले राज्य के ऐसे 980 आश्रम विद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों पर लागू नहीं थी। चूँकि इन कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कुछ कर्मचारियों ने न्यायालय में याचिकाएँ दायर की हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू संशोधित सेवाकालीन आश्वासन योजना को लागू करने की माँग कई बार विधानमंडल में की गई। अतः, अन्य पिछड़ा वर्ग बहुजन कल्याण विभागों के आवासीय आश्रम विद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए स्कूल शिक्षा एवं खेल विभाग द्वारा अनुमोदित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों हेतु दो लाभों सहित संशोधित सेवाकालीन आश्वासन योजना को, गैर-शिक्षण कर्मचारियों हेतु दो लाभों सहित संशोधित सेवाकालीन आश्वासन योजना की तर्ज पर लागू करने का निर्णय लिया गया। यह योजना 1 जनवरी, 2024 से लागू होगी। यह योजना पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होगी और कोई बकाया देय नहीं होगा।

विद्युत करघा उद्योगों को बिजली सब्सिडी योजना का लाभ मिलेगा, वस्त्र आयुक्तालय के पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

राज्य में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए वस्त्र नीति 2023-28 की घोषणा की गई। इसके अनुसार, विद्युत करघा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बिजली सब्सिडी योजना की घोषणा की गई है। इस सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए, मंत्रिमंडल की बैठक में विद्युत करघा उद्योग के लिए वस्त्र आयुक्तालय के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।

एकीकृत एवं सतत वस्त्र नीति, 2023-28 के अंतर्गत इस रियायत का लाभ उठाने के लिए, विद्युत करघा उद्योगों को छह माह के भीतर आयुक्तालय के पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। ऐसा न करने पर वे बिजली सब्सिडी रियायत का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

इसके अलावा, आज की बैठक में 20 लाख रुपये की सब्सिडी लागू करने को मंजूरी दी गई। सहकारी कताई मिलों के समान, औद्योगिक क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत अकोला जिले में एक और धुले जिले में एक, दो निजी कताई मिलों को 3 प्रति यूनिट की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

सम्पादकीय

जीवनदायिनी मानी जाती है दवा, इस समय बनी हुई है मौत की वजह

किसी बीमारी में दवा जीवनदायिनी हो सकती है। ऐसे में मरीज की जान बचाने के लिए उसके परिजन दवा का बंदोबस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मगर जब कोई दवा ही मौत का कारण बन जाए, तो इसे लापरवाही या जान से खिलवाड़ नहीं तो और क्या कहा जाएगा! मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ है, जहां खांसी की दवा से कई बच्चों की मौत के मामले सामने आए हैं। शासन-प्रशासन की ओर से इन मामलों की गहन जांच कराने का आश्वासन दिया गया है।

इसके अलावा, एक चिकित्सक को गिरफ्तार और कुछ अन्य अधिकारियों को निलंबित किया गया है। साथ ही इस दवा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और संबंधित कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सवाल यह है कि ऐसी कार्रवाई के लिए अक्सर किसी बड़े हादसे का इंतजार क्यों किया जाता है? दवाओं की गुणवत्ता जांच नियमित तौर पर क्यों नहीं की जाती और जो दवाएं बच्चों के लिए प्रतिबंधित हैं, वे बाजार में बिना रोक-टोक कैसे बिक रही हैं?

यह कोई पहली बार नहीं है कि देश में किसी दवा की वजह से कई जानें चली गईं। इससे पूर्व भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। विडंबना यह है कि न तो सरकार एवं प्रशासन और न ही स्वास्थ्य संस्थानों एवं वहां कार्यरत अधिकारियों के स्तर पर ऐसी घटनाओं से कोई सबक लिया जाता है। मध्य प्रदेश में जिस चिकित्सक को गिरफ्तार किया गया है, उस पर आरोप है कि वह सरकारी सेवा में होने के बावजूद एक निजी क्लिनिक में भी अपनी सेवाएं दे रहा था और बच्चों के लिए इस दवा के इस्तेमाल का परामर्श देता था।

सवाल है कि आरोपी चिकित्सक के सरकारी सेवा के साथ निजी क्लीनिक में काम करने पर स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है किस दवा के विभिन्न आयु-वर्ग के मरीज पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इसकी जानकारी क्या चिकित्सकों को नहीं दी जाती है? या फिर चिकित्सक और दवा कंपनियों के बीच सांठगांठ से इस तरह का गोरखधंधा फल-फूल रहा है? सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

खबरों के मुताबिक, मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखकर वहां स्थित संबंधित दवा निर्माता कंपनी के खिलाफ जांच करने का आग्रह किया था। इसके बाद तमिलनाडु के औषधि नियंत्रक विभाग ने अपनी जांच में इस दवा के निर्माण में मिलावट होने की पुष्टि की थी। जांच रपट में कहा गया कि इसमें 48.6 फीसद 'डायथिलीन ग्लाइकाल' पाया गया, जो जहरीला रसायन है और सेहत के लिए घातक साबित हो सकता है। सवाल है कि इस तरह की खतरनाक दवा को बाजार में बिक्री की अनुमति कैसे दे दी गई? क्या किसी दवा के बाजार में आने से पहले किया जाने वाला नमूना परीक्षण ही काफी है?

अगर बाद में उस दवा के निर्माण में गुणवत्ता मानकों को दरकिनार किया जाता है और उसके सेवन से किसी की जान चली जाती है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कायदे से बाजार में उपलब्ध दवाओं की गुणवत्ता को लेकर समय-समय पर जांच होनी चाहिए और गड़बड़ी मिलने पर जवाबदेही तय कर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि लोगों की जान से खिलवाड़ न हो। इस बात के लिए भी जागरूकता अभियान चलाए जाने की जरूरत है कि कोई बीमारी होने पर आम लोग चिकित्सकों की सलाह से ही दवा लें। साथ ही गरीब और वंचित तबकों की भी अच्छी चिकित्सा प्रणाली तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना सरकार का प्राथमिक दायित्व है।

बिगड़ता अनुपात और बेटियों का जीवन, तमाम प्रयासों के बाद भी भ्रूण हत्या और नवजातों की मौत पर नहीं लग पा रही है रोक

यह एक विचित्र विडंबना है कि पिछले कई दशकों से लगातार स्त्री-पुरुष अनुपात में बढ़ती खाई को लेकर चिंता जताई जाती रही है। इसे रोकने के लिए तमाम जागरूकता अभियानों से लेकर सरकारी कार्यक्रम भी चलाए गए। मगर आज भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की कम या घटती संख्या के प्रति चिंता का स्तर एक ही जगह थम गया लगता है। हालत यह है कि इसके एक मुख्य कारण के रूप में भ्रूण हत्या पर चर्चा तो होती है, उसे रोकने के लिए नियम-कायदे भी बनाए जाते हैं, लेकिन अब भी इसका सहारा लेकर बेटियों को दुनिया में आने से पहले ही रोक देते हैं।

भारत में भ्रूण हत्या मानो आम बात हो चली है। जन्म के बाद लड़कियों को लावारिस छोड़ने अथवा झाड़ियों में फेंकने की भी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। तमाम प्रयासों के बाद भी भ्रूण हत्या और नवजातों की मौत को रोका नहीं जा सका है। जबकि देश में भ्रूण हत्या से लिंगानुपात लगातार बिगड़ रहा है, जिससे आने वाले समय में सामाजिक असंतुलन बढ़ता ही जाएगा। भ्रूण हत्या ऐसी बुराई है, जिसके आंकड़े न केवल डरावने हैं, बल्कि किसी भी संवेदनशील व्यक्ति और समाज को झकझोरते भी हैं।

सरकार के आंकड़ों के आधार पर 'प्यू रिसर्च सेंटर' की एक रपट कहती है कि वर्ष 2000 से 2019 तक भारत में कम से कम 90 लाख भ्रूण हत्या हुईं। इनमें से 86.7 फीसद हिंदुओं (80 फीसद आबादी), 4.9 प्रतिशत सिखों (1.7 फीसद आबादी) और 6.6 फीसद मुसलिमों (14 फीसद आबादी) में दर्ज की गईं। हालांकि बेटे को वरीयता देने में अब कमी आई है, फिर भी देश में गर्भपात जारी हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 0-6 वर्ष आयु वर्ग में प्रति एक हजार लड़कों पर 914 लड़कियां थीं। जबकि वर्ष 1991 में यह अनुपात 945 था। भारत में लिंग अनुपात की कोई अच्छी स्थिति नहीं है। स्पष्ट है कि यह भ्रूण हत्या की ओर ही इशारा करती है। लांसेट की रपट कहती है कि हर वर्ष 2.39 लाख अतिरिक्त बालिका मृत्यु (5 वर्ष से कम) दर्ज की जाती हैं, जो मुख्य रूप से उपेक्षा और कुपोषण के कारण होती हैं।

वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो का आंकड़ा बताता है कि देश में वर्ष 2022 में शिशु हत्या के 63 मामले दर्ज किए गए, जिनमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक 25 मामले थे। कन्या शिशु हत्या के विशिष्ट आंकड़े अलग से नहीं दिए गए। यह संख्या वास्तविकता से बहुत कम हो सकती है, क्योंकि कई मामले उपेक्षा के कारण भुखमरी बता कर दर्ज नहीं होते। असल में कन्या भ्रूण हत्या के आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं, क्योंकि गर्भपात के सभी मामले प्रायः दर्ज नहीं होते। दूसरी ओर नवजात की मौत के मामले भी कम दर्ज होते हैं, क्योंकि इन्हें अक्सर मृत जन्म या प्राकृतिक मृत्यु के रूप में दिखाया जाता है। हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में लिंग अनुपात में भारी असंतुलन है। यह स्थिति गंभीर है। उत्तराखंड में 2019 के दौरान 132 गांवों में तीन महीने तक एक भी कन्या का जन्म नहीं हुआ।

सरकार बाकायदा कानून पारित कर भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इसके बावजूद हालात नहीं बदले। देश में हजारों क्लीनिक ऐसे हैं, जहां आज भी भ्रूण परीक्षण चोरी-छिपे चल रहा है। राज्य सरकारों के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि सभी क्लीनिकों पर नजर रखी जा सके। इसके लिए आम नागरिकों को जागरूक होना होगा और सरकार की मदद करनी होगी। उधर, लड़कियों को जन्म से पहले मारने की प्रथा अब वहां भी प्रचलित हो रही है, जो अब तक इससे बचे हुए थे। जैसी खबरें आ रही हैं, अब जम्मू-कश्मीर में भी स्थिति चिंताजनक है। वहां का श्रीनगर शहर पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की राह पर है। ऐसी ही स्थिति और भी कई शहरों की बन रही है।

लड़कियों के प्रति इस नकारात्मक सोच के गंभीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। यह बेहद चिंता का विषय है। बार-बार गर्भपात से स्त्रियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। यदि लड़कियों की संख्या इसी तरह घटती रही, तो आगे चल कर महिलाओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं बढ़ने का अंदेशा है। विवाह के लिए उनका अपहरण किया जाएगा, उनकी इज्जत पर हमले होंगे। ऐसे में यह एक गंभीर स्थिति होगी। कुल मिला कर लड़कियों की कम संख्या उनके सम्मानजनक जीवन जीने के अवसरों को कम कर देगी और उनसे जुड़ी कई कुप्रथाओं को भी बढ़ावा देगी।

वहीं कई सामाजिक अवधारणाओं के कारण कई परिवार आज भी महिलाओं पर लड़के को जन्म देने का दबाव डालते हैं, ताकि वह वंश का नाम आगे बढ़ा सके और घर का कमाऊ पूत बन सके। असल में एक लड़की का संघर्ष उसी दिन शुरू हो जाता है, जब वह मां के गर्भ में आती है। यह संघर्ष उसके जीवन के एक बड़े हिस्से को निगल जाता है, भले ही उसे इस दुनिया में जीने की इजाजत क्यों न हो। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि कन्या भ्रूण हत्या अब किसी दायरे में सिमटी नहीं रह गई है। शहरी क्षेत्रों और महानगरों में रहने वाले अति आधुनिक और शिक्षित लोग भी गर्भ में ही बालिकाओं की पहचान करा कर उसे खत्म करने में पीछे नहीं हैं। यह बेहद ही दुखद स्थिति है।

लड़कियों की संख्या घटने का एक कारण यह भी है कि सरकार के जनसंख्या नियंत्रण अभियानों में कई कमियां रही हैं। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सरकार ने दो से अधिक बच्चों वाले माता-पिता को कुछ अधिकारों से वंचित कर दिया है। जैसे, तीन बच्चों की मां को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। यदि वह सरकारी कर्मचारी है, तो कई तरह की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसका सीधा असर महिलाओं के प्रति सामाजिक धारणा और संकीर्ण होने के रूप में सामने आता है। यह दुखद सच है कि लड़कियों के अनुपात में गिरावट के कारण कई राज्यों में युवाओं को विवाह के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। ऐसी खबरें आम रही हैं, जिनमें कई गरीब इलाकों के निर्धन परिवारों की लड़कियों को खरीद कर शादी करने के बारे में चिंता जताई जाती है। दलालों के जरिए खरीद-फरोख्त का यह सिलसिला दिनों-दिन बढ़ रहा है। यह निराशाजनक है कि इसे रोकने के लिए किसी भी स्तर पर ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा है।

एक सामाजिक अपराध के रूप में भ्रूण हत्या न केवल बेटियों के जीवन के लिए खतरा है, बल्कि समाज के संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। इसे रोकने के लिए हर परिवार को जागरूक करना होगा, ताकि वे बेटियों को समान अधिकार और सुरक्षा देने की अहमियत को समझ सकें। हमें हर घर तक यह संदेश पहुंचाना होगा कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि देश और समाज की ताकत हैं। हमें उनके जन्म का उत्सव मनाना होगा और उनके शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। कोई दोराय नहीं कि भ्रूण हत्या से लिंगानुपात बिगड़ रहा है, जिससे आने वाले समय में सामाजिक असंतुलन बढ़ जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि कन्या शिशु का स्वागत करें और उनका पालन-पोषण तथा शिक्षा सुनिश्चित करें। इस तरह की सोच से ही हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। हमें इस दिशा में एकजुट होकर काम करना होगा, ताकि हर बेटी सुरक्षित माहौल में पल कर आगे बढ़ सके।

पाठ्यक्रम की राजनीति में कहीं खो गया हमारा कौशल, पढ़ाई छोड़ने की भी आ जाती है नौबत

शिक्षा का मुख्य आधार पाठ्यक्रम होता है। सरकारें हर कुछ अंतराल पर पाठ्यक्रम के विषय में बदलाव करती हैं, तो इससे कई बार असमंजस की स्थिति बन जाती है। नई शिक्षा नीति 2020 में हमने संकल्प लिया था कि वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम पचास फीसद विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान कर देंगे। यह भी तय किया गया था कि इसके लिए लक्ष्य और समय सीमा के साथ एक स्पष्ट कार्ययोजना भी विकसित कर लेंगे। मगर ऐसा लगता है कि पाठ्यक्रम की राजनीति में हमारा कौशल कहीं खो गया। हम पिछले पांच वर्षों में इस पर चर्चा के बजाय इस तरह पाठ्यक्रम निर्माण के उधेड़बुन में उलझ गए कि किस विषय को हटाना है, कौन-सा विषय जोड़ना है और किस विषय से भविष्य का मतदाता तैयार होगा।

जब कौशल की बात की जाती है या किसी व्यावसायिक शिक्षा की बात होती है, तो हमारे पाठ्यक्रम निर्माता यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि इस तरह की कोई मांग कहीं से आती नहीं। जबकि वे इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाते कि पाठ्यक्रम में जो विषय निर्धारित किए जाते हैं, उसकी मांग या आवाज कहां से आई है? व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम होने के पीछे प्रमुख कारण और तथ्य यह है कि हम मुख्य रूप से कक्षा आठ से ऊपर के विद्यार्थियों के कौशल की बात ही नहीं कर पाते।

व्यावसायिक शिक्षा न मिल पाने के कारण अधिकतर विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति अरुचि रहती है, जिससे बीच में पढ़ाई छोड़ने की नौबत भी आती है। हमारे पाठ्यक्रम और प्रवेश के मानदंड भी व्यावसायिक शिक्षा की योग्यता वाले विद्यार्थियों के लिए अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से तैयार नहीं किए जाते। यही कारण है कि देश के अन्य लोगों के सापेक्ष 'मुख्य धारा की शिक्षा' या अकादमिक शिक्षा से विद्यार्थी वंचित रह जाते हैं। व्यावसायिक शिक्षा के विषयों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए हमारी शिक्षा नीति में सीधे-सीधे कौशल के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के रास्ते पूरी तरह बंद हैं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के अनुमान के अनुसार, उन्नीस से चौबीस आयुवर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल के अत्यंत कम, मात्र पांच फीसद लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की थी, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में बावन फीसद, जर्मनी में पचहत्तर फीसद और दक्षिण कोरिया में तो छियानबे फीसद ने व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की। भारत में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में तेजी लाने की आवश्यकता को पूरी स्पष्टता से रेखांकित किया जाना चाहिए। सरकार और शिक्षाविदों को पाठ्यक्रम की राजनीति छोड़कर व्यावसायिक शिक्षा को पीछे धकेलने की प्रवृत्ति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।

कौशल को पाठ्यक्रम में शामिल करने से पहले और व्यावसायिक कौशल बढ़ाने के लिए हमें एक जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्थानीय परिवेश और मांग के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। हम पाठ्यक्रम एक जैसा पढ़ा सकते हैं, लेकिन कौशल विकसित करने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्थानीय जरूरत, मांग और बाजार के अनुसार ही निर्धारित करना होगा। अन्यथा यह वैसा ही होगा, जैसा पाठ्यक्रम में राजनीति होती है। बाजार को समांतर रखते हुए हमें विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा देने पर विचार करना होगा।

आने वाली भावी पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति से परिचित होना ही चाहिए, लेकिन भारतीय इतिहास की उतनी ही जानकारी हमारे विद्यार्थियों को होनी चाहिए, जो सच-सच लिखा गया है। इतिहास बदलने और परंपराओं को परोसने का काम सरकारों को पाठ्यक्रम की राजनीति से दूर रखना होगा। सवाल है कि अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो इससे हम कैसा ज्ञान और कैसी संस्कृति सिखाना चाहते हैं। यह जरूरी है कि बढ़ती आबादी और बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए आने वाली पीढ़ी को व्यावसायिक कौशल के माध्यम से हुनरमंद बनाया जाए। आजादी के बाद 'हर हाथ को काम मिले, हर व्यक्ति को रोटी मिले', जैसे नारे हमने दिए थे, उसे विद्यार्थियों तक हम पहुंचा नहीं सके। इसलिए यह जरूरी है कि हमारा पाठ्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा से ओतप्रोत हो, ताकि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद विद्यार्थी अपनी रुचि का व्यवसाय प्रारंभ कर सके। विद्यार्थी परिवार पर बोझ न बने, बल्कि परिवार, समाज और देश के आर्थिक विकास में सहयोगी बन सके। यह सब माध्यमिक शिक्षा से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के दौरान ही संभव है। शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार की शिक्षा देना भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। पूरे इतिहास में दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय के साक्ष्य और अध्ययन से पता चलता है कि सर्वोत्तम शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया जहां अनुसंधान और ज्ञान सर्जन की मजबूत संस्कृति रही है, वही विश्वविद्यालय श्रेष्ठ साबित हुए हैं। नई शिक्षा नीति में विभिन्न विषयों में अनुसंधान और भारतीय ज्ञान सर्जन की परंपरा को पाठ्यक्रम में शामिल करने और दुनिया की अर्थव्यवस्था में अनुसंधान तथा नवाचार का नेतृत्व करने के लिए हमें उसकी गुणवत्ता को भी देखना होगा। उच्चतर शिक्षण के तहत गुणात्मक शोध की मानसिकता को मजबूत करने की जरूरत होनी चाहिए। हमारा कौशल वैज्ञानिक और चिंतनशील अनुसंधान को मान्यता देने और उच्च अनुसंधान को स्थापित करने से ही संभावनाएं विकसित करेगा, न कि पाठ्यक्रम में राजनीति से।

ताकि दवा जहर बन फिर से मासूमों की मौत न बने

दो राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से जुड़ी बच्चों की मौत की घटनाएं देश की दवा नियामक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। यह केवल एक चिकित्सा त्रुटि या आकस्मिक दुर्घटना नहीं, बल्कि उस तंत्र की विफलता का प्रतीक है जिस पर जनता अपने जीवन की रक्षा के लिए भरोसा करती है। दवा जैसी जीवनदायी वस्तु में भी जब लालच, लापरवाही या भ्रष्टाचार घुसपैठ कर जाते हैं तो वह अमृत भी विष बन जाता है। बच्चों की मासूम जानें जब घटिया या मिलावटी दवा के कारण चली जाती हैं, तो यह केवल परिवारों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की नैतिकता एवं विश्वास की मृत्यु होती है। कफ सिरप में पाए गए विषैले तत्व-जैसे डाइएथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल, पहले भी कई देशों में सैकड़ों बच्चों की जान ले चुके हैं। फिर भी बार-बार ऐसे हादसे होना इस बात का प्रमाण है कि भारत की दवा नियामक व्यवस्था में संरचनात्मक खामियां बनी हुई हैं। सवाल है कि पिछली गलतियों से क्या सीखा गया? भारत में बने कफ सिरप पहले भी सवालों में आ चुके हैं। 2022 में गाम्बिया में कई बच्चों की मौत के बाद डब्ल्यूएचओ ने एक भारतीय कंपनी के कफ सिरप को लेकर चेतावनी जारी की थी। इसके बाद भी कई और जगहों से इसी तरह की शिकायत आई।

दवाओं के उत्पादन में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। करीब 200 देशों में यहां से दवाएं निर्यात होती हैं और जेनेरिक दवाएं सबसे ज्यादा यहीं बनती हैं। इन उपलब्धियों के बीच इन दो प्रमुख राज्यों में कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत शर्मनाक एवं त्रासदीपूर्ण है। इससे स्पष्ट है कि दवा के क्षेत्र में जिस तरह की निगरानी, मानक और सुरक्षा उपायों की जरूरत है, उसमें कोताही बरती जा रही है। दवा के रूप में जहर धडल्ले से मासूमों की मौत का कारण बन रहा है। इस घटना सामने आने के बाद कार्रवाई का दौर भले ही जारी है। दवाएं वापस ली गई हैं, केस दर्ज हुआ है और नैशनल रेगुलेटर अथॉरिटी ने कई राज्यों में जांच की है। इन घटनाओं से साफ है कि दवा निर्माण की प्रक्रिया में कच्चे माल के स्रोत से लेकर तैयार उत्पाद की गुणवत्ता जांच तक हर स्तर पर लापरवाही व्याप्त है। कई कंपनियां लागत घटाने के लिए औद्योगिक ग्रेड के सॉल्वेंट या रसायनों का प्रयोग कर लेती हैं जो मानव उपभोग के लिए निषिद्ध होते हैं। वहीं निरीक्षण और परीक्षण की सरकारी व्यवस्था न केवल कमज़ोर है बल्कि अक्सर प्रभावशाली कंपनियों के दबाव में निष्क्रिय भी हो जाती है। राज्य और केंद्र स्तर के दवा-नियामक विभागों में पर्याप्त संसाधन और तकनीकी क्षमता का अभाव है, जिससे समय पर निगरानी और सैंपल परीक्षण संभव नहीं हो पाता। जब निरीक्षण औपचारिकता बन जाए और रिपोर्टें खरीद-फरोख्त की वस्तु बन जाएं, तब ऐसी त्रासदियां स्वाभाविक हैं। तमिलनाडु की दवा कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप के नमूने में 48.6 प्रतिशत डाई एथिलीन ग्लाइकॉल मिला है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार इसकी मात्रा 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह एक खतरनाक इंडस्ट्रियल केमिकल है, जिसका इस्तेमाल गाड़ियों और मशीनों में होता है। इसकी वजह से पीड़ित बच्चों की किडनी फेल हो गई।

इन घटनाओं ने न केवल स्वास्थ्य प्रशासन की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाई है बल्कि भारत की वैश्विक छवि पर भी धब्बा लगाया है। पिछले वर्षों में अफ्रीकी देशों में भी भारतीय सिरप से हुई मौतों के बाद कई देशों ने हमारे फार्मा उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया था। अब घरेलू स्तर पर घटित ऐसी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि हमने उन हादसों से कोई सबक नहीं लिया। दुनिया के सबसे बड़े जेनेरिक दवा उत्पादक देश के रूप में भारत को यह मानना होगा कि केवल उत्पादन की मात्रा नहीं, बल्कि गुणवत्ता ही हमारी असली ताकत होनी चाहिए। इस संकट का सबसे पीड़ादायक पहलू यह है कि इसका शिकार वे मासूम बच्चे बने जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अभी विकसित नहीं हुई थी और जिनकी जीवन रक्षा का उत्तरदायित्व समाज और राज्य पर है। इन मौतों की नैतिक जिम्मेदारी केवल दोषी कंपनियों पर नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र पर है जिसने नियमन और नैतिकता की आंखें मूंद लीं। दवाओं में मिलावट या गलत प्रमाणपत्र देना कोई साधारण अपराध नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ किया गया घोर अपराध है। इस पर कड़े से कड़ा दंड होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी निर्माता या अधिकारी ऐसी हरकत करने से पहले सौ बार सोचे। भारत के फार्मास्युटिकल मार्केट का आकार लगभग 60 अरब डॉलर है। इसका बड़ा हिस्सा छोटी कंपनियों के पास है। सीडीएसीओ ने इस साल अप्रैल की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ज्यादातर छोटी और मझोली कंपनियों की दवाएं जांच में तयशुदा मानक से कमतर पाई गईं। इस जांच में 68 प्रतिशत एमएसएमई फेल हो गई थीं। इससे पहले, जब केंद्रीय एजेंसी ने 2023 में जांच की, तब भी 65 प्रतिशत कंपनियों की दवाएं सब-स्टैंडर्ड मिली थीं। प्रश्न है कि यह तथ्य सामने आने के बाद आखिर सरकार क्या सोच कर इन दवाओं को बाजार में विक्रय क्यों जारी रहने दिया? क्यों ऐसे हादसे होने दिये जाते रहे? यह आवश्यक है कि दवा उद्योग में कच्चे माल की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित की जाए, हर बैच की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो और दवाओं के मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर के हों। केंद्र और राज्य सरकारों को ड्रग इंस्पेक्टरों की संख्या और प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ानी चाहिए। हर कंपनी के लाइसेंस नवीनीकरण के समय उसकी पिछली गुणवत्ता रिपोर्ट और परीक्षण परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए। जिन कंपनियों ने सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया है, उनके लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिए जाने चाहिए और शीर्ष प्रबंधन को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। केवल प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं, बल्कि इन मामलों में आपराधिक जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी है। इसके साथ ही चिकित्सा जगत और समाज को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। डॉक्टरों को यह समझना होगा कि शिशुओं को ओटीसी- ऑवर दी कॉउन्टर दवाएं देना कितना खतरनाक हो सकता है। सरकार द्वारा जारी परामर्श और चेतावनियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है। मीडिया को भी सनसनी से ऊपर उठकर जनता को जागरूक करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। इन त्रासदियों को केवल समाचार बनाकर भुला देना नहीं, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य-सुधार के आंदोलन में बदलना समय की मांग है। क्योंकि सरकारी अनुमान से इस साल देश का दवा निर्यात 30 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। वहीं, 2030 तक फार्मा मार्केट के 130 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन, इसके साथ चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। दवाओं की जांच और निगरानी अभी तक की कमजोर कड़ी साबित हुई है। केंद्रीय और राज्य की नियामक एजेंसियों को ज्यादा बेहतर तालमेल के साथ, पारदर्शिता, ईमानदारी और ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि यह मामला केवल इकॉनमी या देश की छवि ही नहीं, अनमोल जिंदगियों से जुड़ा है।

अंततः यह घटना हमें याद दिलाती है कि जीवन रक्षा के साधनों में जब नैतिकता का अभाव हो जाता है तो प्रगति की समूची इमारत ध्वस्त हो जाती है। दवा उद्योग में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और मानवीय संवेदनशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। सरकार और समाज दोनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी बच्चे की जान किसी घटिया या मिलावटी दवा के कारण न जाए। जब तक दवा बनाने वाला और दवा बांटने वाला अपनी जिम्मेदारी को धर्म, करुणा, विश्वास और ईमानदारी की दृष्टि से नहीं देखेगा, तब तक ऐसी त्रासदियां दोहराई जाती रहेंगी। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम दवा नहीं, दायित्व बनाएं, नियमन नहीं, निष्ठा पैदा करें और इस मानवता विरोधी अपराध के लिए दोषियों को उदाहरण स्वरूप कठोरतम दंड दें ताकि भविष्य में जीवन रक्षक औषधि फिर से विश्वास की प्रतीक बन सके।

नीबी कला में कल से प्रारंभ होगी सप्तदिवसीय संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा

थरवई (प्रयागराज)। झूंसी क्षेत्र के नीबी कला गांव में श्रद्धा और भक्ति का महापर्व कल से आरंभ होने जा रहा है। गांव स्थित कृष्णा पैलेस, लीलापुर रोड पर सप्त दिवसीय संगीतमय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन सुनिश्चित किया गया है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कथा का शुभारंभ गुरुवार 9 अक्टूबर से होगा और यह 15 अक्टूबर तक चलेगी। आयोजन के मुख्य यजमान पंडित चक्रधर मिश्र एवं मीरा मिश्र हैं, जिनके संयोजन में यह दिव्य कथा संपन्न होगी। व्यास पीठ से अयोध्या धाम के जगद्गुरु स्वामी राघवाचार्य जी महाराज अपनी अमृतमयी वाणी के माध्यम से भक्तों को श्रीकृष्ण लीला, भक्ति, धर्म और ज्ञान का उपदेश देंगे। कथा का समय प्रत्येक दिन अपराह्न 3 बजे से सायंकाल 7 बजे तक निर्धारित किया गया है।कथा स्थल पर पंडाल, प्रकाश व्यवस्था और श्रद्धालुओं के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। कथा के दौरान प्रतिदिन भक्ति संगीत और संकीर्तन की भी विशेष प्रस्तुति दी जाएगी।इस संबंध में पंडित कमला निवास मिश्र एवं पंडित विद्याधर मिश्र ने बताया कि यह आयोजन समस्त ग्रामवासियों की आस्था का केंद्र होगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों एवं श्रद्धालुओं से अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है।

महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर परमार्थ निकेतन से हार्दिक शुभकामनाएँ, अमर धरोहर 'रामायण' की दिव्य साधना को नमन

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज/ ऋषिकेश। आज हम एक महान संत, आदिकवि और भारतीय संस्कृति के स्तंभ महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर उनकी पुण्य स्मृति को नमन। महर्षि वाल्मीकि ने अपने अद्वितीय ज्ञान, गहन तप और दिव्य दृष्टि से समाज को एक अमूल्य उपहार दिया। 'रामायण' केवल एक महाकाव्य ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। उनके द्वारा रचित रामायण में प्रभु श्रीराम जी की प्रेरणादायक कथाओं के माध्यम से धर्म, सत्य, करुणा, साहस और मानवीय मूल्यों की शिक्षाएँ समाहित हैं। यह दिव्य ग्रंथ भारतीय संस्कृति की आत्मा है।

महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने जीवन के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति, करुणा और मानवता के उच्च आदर्शों का संदेश दिया। उनके द्वारा रचित रामायण में वर्णित प्रत्येक प्रसंग हमें जीवन के नैतिक मूल्यों, कर्तव्यनिष्ठा और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को समझने की प्रेरणा देते हैं। प्रभु श्रीराम जी का चरित्र जीवन में मर्यादा, सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता के आदर्श स्थापित करता है। महर्षि वाल्मीकि जी की दृष्टि और रचनात्मकता ने समाज में नैतिक मूल्यों और संस्कारों के महत्व को उजागर किया, जो आज भी हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं।

महर्षि वाल्मीकि जी की रचना केवल धार्मिक या साहित्यिक दृष्टि

से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व निर्माण और समाज में सदाचार, सहिष्णुता एवं करुणा के संदेश का प्रतीक भी है। उनकी शिक्षाएँ हमें यह संदेश देती हैं कि कठिनाइयों और जीवन की पीड़ा में भी धैर्य, विवेक और साधना के माध्यम से सकारात्मकता और शक्ति का संचार किया जा सकता है। महर्षि वाल्मीकि की यह शिक्षा आज के समय में विशेष महत्व रखती है, जब समाज में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता अधिक है।

स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती केवल उनके जीवन का स्मरण नहीं, बल्कि यह हमें उनके आदर्शों पर चलने का अवसर भी प्रदान करती है। इस पावन अवसर पर यह आवश्यक है कि हम वाल्मीकि-रामायण के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएँ, अपने आचरण में सत्य, धर्म, करुणा और सेवा के सिद्धांतों को शामिल करें। यदि हम अपने जीवन में इन मूल्यों को आत्मसात कर लें, तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होगा, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी यह प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

आज के समय में जहाँ युवा पीढ़ी पर समाज और संस्कृति के उत्थान की बड़ी जिम्मेदारी है, महर्षि वाल्मीकि जी के आदर्शों और रामायण की शिक्षाओं को युवाओं तक पहुँचाना अत्यंत आवश्यक है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में केवल भौतिक उपलब्धियाँ ही नहीं, बल्कि चरित्र, संस्कार और मानवीय मूल्यों का निर्माण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महर्षि वाल्मीकि के शब्द और उनके द्वारा प्रस्तुत जीवन-दर्शन हमारे लिए एक मार्गदर्शक हैं, जो हमें सच्चाई, न्याय और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।

परमार्थ निकेतन की ओर से महर्षि वाल्मीकि जी को कोटि-कोटि नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी अमर रचना रामायण सदैव हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती रहे और हमें सत्य, धर्म, और मानवता के पथ पर चलने की प्रेरणा देती रहे।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान में सफलता

जिला न्यायालयों में रिकॉर्ड स्तर पर मामलों का समाधान, जनजागरूकता और सहभागिता से मध्यस्थता को मिला नया आयाम

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। सभी के लिए न्याय को त्वरित और सुलभ बनाना किसी भी न्याय वितरण प्रणाली का प्राथमिक लक्ष्य है। देश की विशाल जनसंख्या और लगातार बढ़ते विवादों के कारण न्यायपालिका पर बोझ बढ़ता जा रहा है। इसी दिशा में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सहयोग से 'राष्ट्र के लिए मध्यस्थता' नामक विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया गया। यह अभियान 01 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक भारत के सभी तालुका न्यायालयों, जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के मध्यस्थता के माध्यम से निपटारे हेतु 90 दिन का गहन अभियान था।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संजय सिंह प्रथम ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस अभियान के उद्देश्यों को साकार करने के लिए अनेक कदम उठाए। उच्च न्यायालय में वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक अनादर, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, ऋण वसूली, विभाजन, बेदखली, भूमि अधिग्रहण और अन्य उपयुक्त मामलों की पहचान कर उन्हें मध्यस्थता हेतु भेजा गया। उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, इलाहाबाद और इसकी लखनऊ पीठ में 01 जुलाई 2025

से 30 सितंबर 2025 तक 1, 978 मामले भेजे गए, जिनमें से 100 मामलों का मध्यस्थता के माध्यम से समाधान हुआ।

उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु नियमित ऑनलाइन वर्चुअल बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में जिला न्यायाधीश, विशेष कार्याधिकारी, सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नोडल अधिकारी, पारिवारिक न्यायालयों, वाणिज्यिक न्यायालयों, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरणों के पीठासीन अधिकारी शामिल हुए। अभियान के दौरान जिला न्यायालयों में 01 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक 1, 15, 309 मामले मध्यस्थता के लिए भेजे गए, जिनमें से 13, 250 मामलों का मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा हुआ। अभियान के दौरान आम जनता को प्रिंट, रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मध्यस्थता के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। पोस्टर और बैनर जिला न्यायालय परिसर और प्रवेश द्वारों पर प्रमुख स्थानों पर लगाए गए। साथ ही, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं उनके निवास जिलों में मध्यस्थ के रूप में ली गईं और अतिरिक्त अधिवक्ता मध्यस्थों की नियुक्ति की गई।

राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान की सफलता आम जनता को मध्यस्थता के महत्व के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी और ए0डी0आर0 तंत्र के माध्यम से विवादों के सक्रिय समाधान के लिए प्रेरित करेगी।

राष्ट्र साधना में रत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 वर्ष : भाजपा

भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके सफल शासन काल के 24 वर्ष पूर्ण होने पर दी बधाई

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। भाजपा मुट्ठीगंज मंडल अध्यक्ष परमानंद वर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफल शासन के 24 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी गई इस अवसर भाजपा प्रवक्ता राजेश केसरवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ही के दिन गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब से आज तक उन्होंने ने अपने 24 वर्ष के शासन काल में उन्होंने जनसेवा को साधना और राष्ट्र निर्माण को अपना ध्येय बनाकर अपने अद्वितीय नेतृत्व, अटूट संकल्प और असीम ऊर्जा से आपने भारत को एक नई दिशा और पहचान दी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंडल अध्यक्ष परमानंद वर्मा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में गरीब, युवा, महिला और किसान सशक्तिकरण से लेकर आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, नवाचार, डिजिटल क्रांति और समावेशी विकास तक- आपके मार्गदर्शन में राष्ट्र ने नई ऊँचाइयाँ प्राप्त की हैं।

संचालन मंडल महामंत्री सुधांशु त्रिपाठी ने किया बधाई देने वालों में सुनील केसरवानी, अभिषेक जायसवाल जितेंद्र जायसवाल, सौरभ चौरसिया, अजय अग्रहरि, कमलेश कुमार, मंजू गुप्ता, मालती केसरवानी, अन्नपूर्णा श्रीवास्तव, दीपक केसरवानी, अनिल गुप्ता, आलोक वैश्य, रोहित भारतीय, दीपक केसरवानी, शत्रुघ्न जायसवाल, नीरज केसरवानी, आदि रहे।

थरवई का ऐतिहासिक दशहरा मेला संपन्न, कलात्मक चौकियों ने मोहा मन

मंत्र भारत संवाददाता

थरवई (प्रयागराज)। परंपराओं और धार्मिक उत्साह के संग थरवई क्षेत्र का प्रसिद्ध दशहरा मेला इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। आदर्श रामलीला कमेटी चक ठाकुर राम, जगदीशपुर पूरे चंदा, थरवई के तत्वावधान में आयोजित इस ऐतिहासिक मेले में हजारों की संख्या में लोग उमड़े।मेले में आधा दर्जन से अधिक कलात्मक चौकियां निकाली गईं, जिनकी सजावट और आकर्षक झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। बच्चों के लिए झूले, खिलौने और चार्ट जैसी कई मनोरंजक सामग्री लगाई गई थी। वहीं, महिलाओं ने घरेलू सामान और सजावटी वस्तुओं की जमकर खरीदारी की।मेले की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए थरवई प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार पांडे पुलिस टीम के साथ सतर्क रूप से मौजूद रहे। पूरे आयोजन के दौरान शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहा।कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से के. डी. मिश्रा, बी डी शुक्ला जिलेदार शुक्ला श्याम तिवारी ननकू शुक्ला सहित अन्य सम्मानित नागरिक शामिल रहे।

आरएसएस द्वारा विजयदशमी पर्व पर जागरण का किया गया आयोजन

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। हिंदू समाज में पौरुष तथा शक्ति का जागरण श्री विजयदशमी के पावन पर्व पर होता है इसी पवित्र पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य प्रारंभ होकर 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है यह उद्बोधन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीष्म शाखा केशव नगर प्रयाग दक्षिण में सहभाग बौद्धिक प्रमुख श्री कुंवर जी ने कहा अब तक संघ के पांच सरसंघचालक हो चुके हैं वर्तमान में डॉ मोहन भागवत जी हैं विचार करिए, शून्य से कार्य प्रारंभ करना कितना कठिन होता है जहां कुछ भी ना हो वहां डॉक्टर हेडगेवार जी ने कितना सोचा होगा यह भूमि , देवभूमि भारत भूमि, जहां देवता भी अवतार लेने के लिए, आने के लिए लालायत रहते हैं इस भूमि में जब-जब कोई संकट आता है देव स्वयं अवतार लेकर उस संकट से मुक्ति दिलाते हैं जब-जब धर्म पर संकट आता है ईश्वर ही मुक्ति दिलाते हैं यह रामचरितमानस में कहा गया है–

'' जब जब होई धरम की हानि ! बाढहि , असुर अधम अभिमानी''

इसी प्रकार भागवत गीता में भी कहा गया है '' यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ? '' जो भी धर्म के लिए कार्य करता है वह ईश्वरीय कार्य होता है संघ का स्वयंसेवक यही कार्य करता है अपने भारत माता को सर्वोपरि मानते हैं

समय-समय की बात है कभी देव स्वयं आते हैं, कभी अपने प्रतिनिधि के रूप में , संगठन के रूप में , व्यक्ति के रूप में , किसी भी जाए तो उसको कैसे हम बचा के आगे तक ले जाएं क्योंकि समाज

न किसी को भेजते हैं? डॉक्टर हेडगेवार भी उस ईश्वरी कार्य को करने के लिए आए हैं 100 वर्ष पूर्व उनकी दूरदर्शिता कितनी तीव्र रही होगी कि हमें आजादी अगर मिल बड़ा विस्मित समाज था? डॉक्टर हेडगेवार ने 17 बंधुओं के साथ संघ की स्थापना की लगभग 1 वर्ष तक विचार विमर्श होता रहा संघ को क्या करना चाहिए उस समय भी राय देने वालों की कमी नहीं थी आज भी नहीं है पर करना क्या है यह स्पष्ट करने वाला कोई नहीं रहता त डॉक्टर साहब स्वयं एमबीबीएस डॉक्टर थे इसलिए उस समय उनके साथ डॉक्टर, इंजीनियर , शिक्षाविद सभी लोग जुड़ गए पर समाज का सहयोग नहीं मिला उन्होंने छोटे बच्चों से ही अपना कार्य प्रारंभ किया उन्हें एक छोटे से स्थान मोहिते बाड़ा मैं खेल खिलाने का कार्य प्रारंभ किया उसे समय लोग उनका उपहास उड़ाते थे की बच्चों से कोई संघ चलेगा पर आज उनका दिखाए मार्ग 100 वर्ष पूर्ण कर लिया डॉक्टर साहब की संकल्पना थी 'एक अखंड भारत' उसी के लिए वह कार्य भी करते रहे उनके बाद इस कार्य को गुरु जी ने आगे बढ़ाया गुरु जी के देहांत 1973 के बाद बालासाहेब देवरस जी ने उसे गति दी? उन्हें लगा हम सेवा के माध्यम से भी समाज में जागरूकता ला सकते हैं उन्होंने सामाजिक अस्पृश्यता को भी नकारा कहा यह समाज के लिए हानिकारक है उन्होंने संघ में सुभाषित की भी शुरुआत कराई–

'' हिन्दवः सोदराः सर्वे, न हिन्दूः पतितो भवेत्।

मम दीक्षा हिन्दू रक्षा, मम मंत्रः समानता।।''

भावार्थ : सब हिन्दू भाई है, कोई भी हिन्दू पतित नहीं है। हिंदुओंकी रक्षा मेरी दीक्षा है, समानता यही मेरा मंत्र है।

हम सभी भारत माता के ही संतान हैं हम सब एक ही माता के उधर से पैदा हुए हैं एक ही संसाधन से आगे बढ़े हैं पुष्पित पलवित बढ़े हुए हैं।

मुशायरा : यहां रहकर जो लगाता है पाकिस्तान के नारे। वह कभी सच्चा मुसलमां हो नहीं सकता

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी व अल हुदा एजुकेशन सोसायटी का एक शाम शहीदों के नाम मुशायरे में शायरों ने भरे क़ौमी यकजहती के रंग में श्रोताओं को झूमने पर कर दिया मजबूर , जमकर मिली वाह वाही।

अल हुदा एजूकेशनल सोसायटी के संयोजन में प्रयागराज के हिन्दुस्तानी अकेडमी सभागार में मुशायरे का आग़ाज़ मुख्य अतिथि प्रख्यात गाईनोलाजिस्ट डॉ नाज़ फात्मा विशिष्ट अतिथि डॉ मोनिका शर्मा व मेराज अहमद की उपस्थिति व डॉ ब्राज़िल हाशमी की अध्यक्षता में सभी ने एक सुर में राष्ट्रगान गाकर मुशायरा का आग़ाज़ किया।शायर व अंतराष्ट्रीय संचालक नजीब इलाहाबादी के संचालन में सबसे पहले अल हुदा एजूकेशनल सोसायटी के कनवीनर इन्तजार आब्दी व शफक़त अब्बास

पाशा द्वारा मुख्य अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट करने के साथ शॉल ओढ़ाकर व मोमेन्टो देकर सम्मानित किया गया।वहीं एक दर्जन से अधिक ख्यातिप्राप्त शायरों व कवियों ने देश की एकता और अखंडता तथा देश पर क़ुर्बान होने वाले रणबांकुरों को समर्पित रचनाओं और काव्यांजलि से याद किया।खूब तालियां बजीं।वहीं मखदूम फूलपूरी ने क़ौमी यकजहती पर कलाम पेश करते हुए पढ़ा।दिलों दिमाग़ में भर दे जो आग नफरत कि।

कभी बच्चों को ऐसी किताब मत देना! कवयित्री नीलिमा मिश्रा ने स्वार्थी लोगों पर कविता के माध्यम से प्रहार करते हुए कहा।क्या बुरा है सही सही कहना। दिल्लगी हो तो दिल्लगी कहना।हो जो मतलब तो लोग मिलते हैं।ऐसे रिश्तों को मतलबी कहना।तुम पे कहती हूं एक ग़ज़ल अब मैं।तुम इसे चाहे आशीक़ी कहना।युवा शायरा मिस्बाह इलाहाबादी नेआज के हालात पर पढ़ा इश्क़ में होशियारी नहीं चाहिये। नफरतों का पुजारी नहीं चाहिये।प्यार को एक तिजारत जो समझे यहां। प्यार का वह भिखारी नहीं चाहिए।शायर फरमूद इलाहाबादी, शहंशाह सोनवी, मखदूम फूलपूरी, अशरफ लखनवी, किरदार ग़ाज़ीपुरी, नीलीमा मिश्रा, वंदना शुक्ला, मिस्बाह इलाहाबादी, शादाब बनारसी, सुहेल ग़ाज़ीपुरी, जावेद शोहरत ने अपनी उच्च कोटि की रचनाओं से श्रोताओं का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने व लोगों के सुख दुख समृद्धि में अग्रणी भूमिका निभाने वाले समाजसेवीयो को अल हुदा एजूकेशनल सोसायटी की ओर से सम्मानित किया गया। कोरोनाकाल में समाजसेवा के ज़रीए दिवंगतों का कफन दफ्न में बढ़ चढ़ कर समर्पित रहकर कीर्तिमान स्थापित करने वाले समाजसेवी शफक़त अब्बास पाशा को विशेष सम्मान देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आसिफ उस्मानी, वज़ीर खां, एस ए खान, इफ्तेखार आलम, डॉ मज़हर अब्बास, सैय्यद मोहम्मद अस्करी , अफसर महमूद , अज़मत अब्बास , जैनुल अब्बास आदि श्रोतागण उपस्थित रहे।

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने बोलेरो की नई रेंज पेश की

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। भारत की अग्रणी एसयूवी विनिर्माता, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने आज बोलेरो की नई रेंज पेश की। नई बोलेरो की कीमत 7.99 लाख (शोरूम में) से शुरू होती है, और नए पेश किए गए टॉप-एंड बी8 वेरिएंट की कीमत 9.69लाख (शोरूम में) है। नई बोलेरो नियो की शुरुआती कीमत 8.49लाख (एक्स-शोरूम) है, जबकि नए टॉप-एंड वेरिएंट एन11 की कीमत 9.99लाख (एक्स-शोरूम) है। इस लॉन्च के साथ, बोलेरो रेंज खूबसूरती, अधिक आराम और आधुनिक सुविधाओं के साथ अपना विशिष्ट आकर्षण बरकरार रखे हुए है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के ऑटोमोटिव डिवीजन के मुख्य कार्यकारी, नलिनीकांत गोलागुंटा ने कहा, 'बोलेरो समय की कसौटी पर खरी उतरी है और 25 साल से भी अधिक समय से भारत की सबसे बहुमुखी तथामज़बूत एसयूवी में से एक के रूप में अपनी जगह बनाए हुए है। इस स्थायी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, नई बोलेरो रेंज को गतिशील और तेज़ी से विकसित हो रहे नए भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। मज़बूती, समकालीन स्टाइल, अधिक आराम और आधुनिक सुविधाओं के शानदार मेल के साथ, नई बोलेरो और बोलेरो नियो शक्तिशाली एसयूवी का अनुभव प्रदान करती हैं जो शहरी परिवेश और चुनौतीपूर्ण इलाकों में समान रूप से कारगर है।'

बोलेरो अपनी 25 साल की विरासत और 16 लाख से ज़्यादा संतुष्ट ग्राहकों के साथ, बहुउपयोगी एसयूवी बनी हुई है। यह शहर की व्यस्त सड़कों से लेकर ऊबड़-खाबड़ सड़कों वाले ग्रामीण इलाकों तक, विविध इलाकों में बेहतरीन प्रदर्शन करती है और असाधारण अनुकूलनशीलता तथा मूल्य प्रदान करती है।

अशोक नगर में जमीन खुदाई के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल, आसपास की इमारतों में आईं दरारें

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका मुख्यालय के समीप अशोक नगर क्षेत्र में बिल्डिंग निर्माण कार्य कर रहे शक्ति बिल्डर एंड डेवलपर पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि बिल्डर ने इमारत निर्माण के लिए डायनामाइट ब्लास्ट कर पत्थर तोड़ने का कार्य किया,जिससे आसपास की कई इमारतों में दरारें आ गईं और क्षेत्र में भय का माहौल बन गया है,स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ब्लास्टिंग के दौरान इतनी तेज कंपन होती हैं कि इमारतों की दीवारों में दरारें और प्लास्टर टूटने लगे हैं। पिछले एक वर्ष से बिल्डर की ओर से बड़े पैमाने पर खुदाई और पत्थर निकालने का कार्य जारी है। इससे पहले भी भिवंडी पालिका प्रशासन ने सड़क पर गंदगी फैलाने के लिए बिल्डर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। नागरिकों ने इस घटना की शिकायत ठाणे जिला अधिकारी, भिवंडी पालिका आयुक्त और नगर विकास विभाग को की है। शिकायत के बाद जिलाधिकारी कार्यालय के कर व प्रशासकीय अधिकारी जगदीश देवकर ने मनपा उपायुक्त बिक्रम दराडे को तत्काल जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मनपा प्रशासन ने गंभीरता को देखते हुए अभियंताओं की एक विशेष टीम गठित कर दी है, जिसे निर्माण स्थल का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।पालिका के सहायक आयुक्त माणिक जाधव ने भी पुष्टि की है कि पत्थर तोड़ने के लिए डायनामाइट ब्लास्ट का उपयोग किया गया था। वहीं, मनपा के आपत्ति व्यवस्थापन प्रमुख सार्किब खर्बे ने नगर रचना विकास विभाग से बांधकाम की मंजूरी से जुड़े कागजात मांगे है।अशोक नगर और आसपास की सोसाइटियों के रहिवासियों, जिनमें अभिषेक कोठारी सहित कई लोग शामिल हैं, ने मांग की है कि निर्माण कार्य तुरंत रोका जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सूत्रों के अनुसार, ब्लास्टिंग के लिए चार डायनामाइट लाए गए थे, जिनमें से दो का ही इस्तेमाल किया गया। अधिक कंपन होने के कारण आगे के ब्लास्ट रोक दिए गए। प्रशासन का कहना है कि जांच जारी है और यदि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित बिल्डर और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना भिवंडी में निर्माण कार्यों की सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

भिवंडी का ग्राम विकास अधिकारी बर्खास्त

1.40 करोड़ के गबन का मामला दर्ज

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी तालुका की खोणी ग्राम पंचायत में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी राम जगन्नाथ म्हस्के पर भारी भ्रष्टाचार और सरकारी निधि के गबन के गंभीर आरोप लगे हैं। जांच में करोड़ों रुपये के हेरफेर का मामला सामने आने के बाद अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, म्हस्के पर वर्ष 2016 से 2017 के बीच किए गए भुगतानों और कार्यों में अनियमितताओं के आरोप हैं। आरोप है कि उन्होंने सरकारी निधि का दुरुपयोग किया, टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी की और कई सरकारी योजनाओं में वित्तीय गड़बड़ी की। कल्याण पंचायत समिति के गट विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक जांच रिपोर्ट में म्हस्के को दोषी पाया गया है।इसके बाद ठाणे विधि लेखा कार्यालय और कोंकण विभाग के सहायक आयुक्त (जांच) द्वारा किए गए स्वतंत्र लेखा परीक्षण में यह खुलासा हुआ कि कुल 1 करोड़ 40 लाख 39 हजार 738 रुपये का गबन किया गया है।इस पूरे प्रकरण का खुलासा तब हुआ जब ग्राम पंचायत सदस्य शाहनवाज इम्तियाज कुरेशी ने ठाणे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास विस्तृत शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर जिला परिषद प्रशासन हरकत में आया और संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यह मामला भिवंडी तहसील में चल रही बड़ी वित्तीय जांच का हिस्सा माना जा रहा है और अधिकारियों को आशंका है कि आने वाले दिनों में और भी कई घोटाले सामने आ सकते है। ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ दर्ज यह मामला स्थानीय शासन में फैले भ्रष्टाचार और जवाबदेही के अभाव की एक और कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद संबंधित अधिकारी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

सीजेआई पर कोर्ट में जूता फेंकने की कोशिश की निंदा, रिपब्लिकन पार्टी (एकतावादी) ने उपविभागीय अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

भिवंडी (संवाददाता) ।सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मा. भूषण गवई पर वकील द्वारा जूता फेंकने की कोशिश की घटना को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (एकतावादी) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषी वकील राकेश किशोर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए अपना ज्ञापन भिवंडी उपविभागीय कार्यालय (एसएडीएम) को सौंपा है।पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विकास एस. निकम ने कहा कि यह कृत्य न केवल न्यायपालिका का अपमान है, बल्कि भारतीय संविधान और न्याय व्यवस्था पर हमला भी है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश देश की न्याय प्रणाली के स्तंभ हैं और उनके प्रति असम्मानजनक व्यवहार लोकतंत्र की मूल आत्मा को ठेस पहुंचाने वाला कदम है।निकम ने कहा कि इस घटना ने न्यायपालिका और पूरे देश के न्यायिक तंत्र की गरिमा को धक्का पहुंचाया है। उन्होंने मांग की कि आरोपी वकील के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाए और न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ दोबारा न हों।रिपब्लिकन पार्टी ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। पार्टी ने सरकार से अपील की कि न्यायिक संस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ। उन्होंने कहा कि ऐसे असंवेदनशील और अनुशासनहीन कृत्य न केवल न्यायिक प्रक्रिया की मर्यादा को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि समाज में गलत संदेश भी देते हैं।इस अवसर पर भिवंडी शहर अध्यक्ष महेबूब बादशाह शेख, अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष आशफाक इसाक शेख, महासचिव वकील राजेन्द्र साठे, युवा अध्यक्ष कल्पेश यशवंत घाडगे, अशोक गायकवाड़ सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। पार्टी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और न्यायपालिका के सम्मान की रक्षा का संकल्प दोहराया।

भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका में आज मंगलवार को महर्षि वाल्मीकि जयंती का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के 18 फरवरी 2025 के परिपत्रक और महानगरपालिका के प्रशासक तथा आयुक्त अनमोल सागर (भा.प्र.से.) के निर्देशानुसार, महानगरपालिका मुख्यालय के तल मंजिल पर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर उन्हें सम्मानित किया गया।इस अवसर पर अतिरीक्त आयुक्त विठ्ठल डाके ने महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उपायुक्त (कर) बालकृष्ण क्षीरसागर, सुरक्षा विभाग प्रमुख राजेश गोसावी, बारनिशी विभाग प्रमुख दीपिका ठाकरे, शौचालय विभाग प्रमुख नितीन चव्हाण के साथ-साथ वाल्मीकि समाज/समाज संयुक्त संस्था शौचालय एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश करौतिया, महेश शोदै, अनिल मरोठिया, सुधीर ठकौलिया, जुगेश शौदै, सुनिल दुपटे, पप्पू दुपटे, बृजपाल जीनवाल, आनंद ढकोलिया, जितेंद्र ढकोलिया, सुमित करोतिया और महानगरपालिका के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।महर्षि वाल्मीकि जयंती के इस आयोजन का उद्देश्य समाज में उनके योगदान और आदर्शों को याद करना और उन्हें सम्मानित करना था।

महाप्रबंधक ने मध्य रेल के 11 कर्मचारियों को संरक्षा पुरस्कार प्रदान किया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

विजय कुमार, महाप्रबंधक, मध्य रेल ने 11 मध्य रेल कर्मचारियों – मुंबई मंडल से 2, पुणे मंडल से 2, सोलापुर मंडल से 2, नागपुर मंडल से 2 तथा भुसावल मंडल से 3 कर्मचारियों – को सेफ्टी अवार्ड प्रदान किया। यह कार्यक्रम 07.10.2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई में आयोजित किया गया।

इन संरक्षा पुरस्कार को कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान उनकी सतर्कता, अनहोनी घटनाओं को टालने में उनके योगदान तथा ट्रेन संचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया गया। प्रत्येक पुरस्कार में एक मेडल, प्रशंसा प्रमाणपत्र, उत्कृष्ट सुरक्षा कार्य का प्रशस्ति पत्र एवं ?2000/- का नगद पुरस्कार शामिल है।

पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का विवरण

मुंबई मंडल

श्री सी. एल. कुरिल, मोटरमैन, कल्याण – दिनांक 15.09.2025 को असनगांव लोकल चलाते समय उन्होंने देखा कि पाँचवीं लाइन के लिए प्रवेश सिग्नल क्रमांक VVH-6 गलती से बंद कर दिया गया था। उन्होंने सिग्नल पार नहीं किया, सभी संबंधितों को सूचित किया और सही सिग्नल मिलने के बाद ही ट्रेन आगे बढ़ाई। उनकी सतर्कता और तीक्ष्ण निरीक्षण ने ट्रेन को गलत ट्रैक पर जाने से रोका।

श्री रवि रंजन कुमार, प्वाइंट्समैन, कल्याण – दिनांक 15.08.2025 को ड्यूटी के दौरान उन्होंने देखा कि एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते समय फिसलकर गिर गया। उन्होंने तुरंत लाल झंडी दिखाकर ट्रेन रुकवाई और यात्री को बचाया।

पुणे मंडल

श्री प्रेम प्रकाश, लोको पायलट (मालगाड़ी), मिरज – दिनांक 10.09.2025 को ड्यूटी के दौरान उन्होंने मसूर और शिरवडे स्टेशनों के बीच अप लाइन पर एक ट्रक देखा। उन्होंने तुरंत सभी संबंधितों को सूचित किया। ट्रेन क्रमांक 17412 कोल्हापुर-सीएसएमटी महालक्ष्मी एक्सप्रेस को सतर्कता आदेश के साथ चलाया गया। उनकी तत्परता ने संभावित दुर्घटना को टाल दिया।

श्री विजय दिनकर पाटिल, सहायक उप-निरीक्षक, आरपीएफ, मिरज – दिनांक 09.09.2025 को ड्यूटी के दौरान उन्होंने देखा कि एक यात्री चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास करते समय गिर गया। उन्होंने तुरंत दौड़कर यात्री को सुरक्षित खींच लिया और उसे गंभीर चोट से बचाया।

सोलापुर मंडल

श्री प्रताप हिरू, प्वाइंट्समैन, वाडी – दिनांक 11.09.2025 को शंटिंग ड्यूटी के दौरान उन्होंने पास की 34 लाइन पर रेल फ्रैक्चर देखा। उन्होंने तुरंत सभी संबंधितों को सूचित किया और संभावित दुर्घटना को टाल दिया।

श्री भँवर सिंह यादव, ट्रैक मेंटेनर, परेवाड़ी – दिनांक 28.07.2025 को ड्यूटी के दौरान उन्होंने भोपालपेट पुल के पास टूटी हुई एंटिटंग रेल देखी। उन्होंने तुरंत ट्रैक की सुरक्षा की और संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। उस समय ट्रेन क्रमांक 22160 चेन्नई-सीएसएमटी सुपरफास्ट पहले ही परेवाड़ी स्टेशन से निकल चुकी थी। उनकी सतर्कता ने संभावित दुर्घटना को टाल दिया।

नागपुर मंडल

श्रीमती रमा चौहान, तकनीशियन (सीएंडडब्ल्यू), आमला – दिनांक 27.07.2025 को मालगाड़ी की रोलिंग जांच के दौरान उन्होंने एक वैगन से असामान्य आवाज सुनी। जांच में एक्सल बॉक्स की बेयरिंग कप टूटी हुई पाई गई। उनकी तीव्र निरीक्षण क्षमता ने संभावित दुर्घटना को रोका।

श्री पवन बछले, सहायक (सीएंडडब्ल्यू), आमला – दिनांक 16.08.2025 को रात्रि ड्यूटी के दौरान उन्होंने चार वैगनों से ज्वलनशील पदार्थ का रिसाव देखा। जांच में पाया गया कि फिलिंग डोम कवर खुला था। उनकी सतर्कता ने संभावित दुर्घटना को रोका।

भुसावल मंडल

संतोष चौधरी, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता, बोडवाड – दिनांक 24.08.2025 को वरंगांव यार्ड में ड्यूटी के दौरान उन्होंने गुजरती मालगाड़ी से असामान्य आवाज सुनी। जांच में 8 टायरों में धातु के जमा कण पाए गए। उनकी सतर्कता ने दुर्घटना को रोका।

रोहित बोरिकर, ट्रैक मेंटेनर, भुसावल – दिनांक 14.09.2025 को स्थिर चौकीदार के रूप में ड्यूटी के दौरान उन्होंने ट्रेन क्रमांक 22137 नागपुर-अहमदाबाद प्रेरणा एक्सप्रेस के एक कोच में ब्रेक बाइंडिंग देखा। उन्होंने तुरंत सूचित किया और संभावित दुर्घटना को टाल दिया।

श्रीनिवास सिंह, तकनीशियन (सीएंडडब्ल्यू), भुसावल यार्ड – दिनांक 17.08.2025 को मालगाड़ी की जांच के दौरान उन्होंने एक वैगन की बोगी बोल्स्टर टूटी हुई पाई। उन्होंने तुरंत सूचित कर संभावित दुर्घटना को रोका।

महाप्रबंधक ने पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सतर्कता और कार्य के प्रति समर्पण अन्य कर्मचारियों को भी प्रेरित करेगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और जन-धन व रेलवे संपत्ति की हानि को रोका जा सकेगा। इस अवसर पर श्री प्रतीक गोस्वामी, अतिरिक्त महाप्रबंधक, श्री चंद्र किशोर प्रसाद, प्रधान मुख्य सुरक्षा अधिकारी तथा अन्य प्रमुख विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

स्कूल में लटका ताला, अंदर से आ रही थी मासूम के रोने की आवाज

नजारा देख लोगों के उड़े होश; बीएसए ने दिए जांच के आदेश

लखनऊ **(एजेंसी)**। कन्हों गांव स्थित एक सरकारी विद्यालय में मानवता को झकझोर देने वाली लापरवाही का मामला सामने आया है। स्कूल की छुट्टी के बाद चार वर्षीय बच्ची को क्लासरूम में ही बंद कर दिया गया। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने शिक्षकों को सूचना दी, जिसके बाद उसे बाहर निकाला गया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। अछल्दा ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी (एबीएसए) को जांच सौंपी गई है। बीएसएने स्पष्ट किया है कि इस गंभीर लापरवाही के लिए जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बच्ची सुरक्षित है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बता दें कि यह घटना अछल्दा क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय कन्हों की है, जहां कक्षा चार का छात्र प्रांशु अपनी छोटी बहन तन्नू (4 वर्ष) को स्कूल लेकर आया था। दोपहर में जब छुट्टी हुई तो सभी बच्चे और शिक्षक स्कूल से चले गए, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि बच्ची क्लास के अंदर ही रह गई है। कुछ देर बाद स्कूल परिसर से रोने की आवाज आई, जिसे सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बच्ची स्कूल में बंद थी। तुरंत शिक्षक को सूचना दी गई। शिक्षक ने पहुंचकर ताला खोला और बच्ची को बाहर निकाला। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

सपा कार्यालय पर बड़ा संकट : 2 सप्ताह में खाली कराने का आदेश, कब्ज़ा अब नगर निगम करेगा

लखनऊ **(एजेंसी)**। सिविल लाइंस स्थित सपा कार्यालय अब प्रशासन की सख्ती के घेरे में आ गया है। जिला प्रशासन ने सपा कार्यालय को दो सप्ताह के भीतर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। यह आदेश पिछले 1 अगस्त को कार्यालय के आवंटन निरस्त करने के बाद आया है और अब इस विवाद ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है सपा कार्यालय, जो कोठी संख्या-4 के नाम से जाना जाता है 13 जुलाई 1994 को तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के नाम 250 रुपये मासिक किराये पर आवंटित किया गया था। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस भवन का नामांतरण सपा द्वारा नहीं किया गया, जिससे अब प्रशासन ने इसे कब्ज़ा लेने का औपचारिक कदम बना दिया है। एडीएम वित्त ममता मालवीय ने सपा जिलाध्यक्ष को पूर्व में भेजे गए नोटिस में साफ कहा था कि भवन को एक महीने के भीतर खाली कर जिला प्रशासन को सौंपें, अन्यथा प्रतिदिन एक हजार रुपये का हर्जाना वसूला जाएगा सत्य यह है कि शासनादेश के अनुसार किसी भी आवासीय या व्यवसायिक भवन का आवंटन 15 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि उक्त सपा भवन को 30 साल से अधिक समय हो चुका है। यही कारण है कि अब प्रशासन ने कार्रवाई का निर्णय लिया और भवन को नगर निगम के कब्ज़े में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सपा जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह ने बताया कि प्रशासन की ओर से प्राप्त नोटिस पर विधिक सलाह ली जा रही है और जल्द ही इसका औपचारिक जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी स्थिति का मूल्यांकन कर रही है और कानूनी मार्ग अपनाएगी मुरादाबाद में इस आदेश के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शहर के राजनीतिक समीकरणों पर इस फैसले का सीधा असर पड़ सकता है। प्रशासन और सपा के बीच संभावित टकराव की आशंका भी जताई जा रही है यह मामला मुरादाबाद के राजनीतिक इतिहास में एक संकेतक घटना के रूप में देखा जा रहा है, जो बताता है

पत्नी से मन भरा तो सास से लगाया दिल, कई बार बनाया शारीरिक संबंध, फोटो वायरल हुई मचा बवाल

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश में इन दिनों प्रेम-प्रसंग और अवैध संबंध से जुड़ी तमाम खबरें सामने आ रही है। अब ऐसा ही एक मामला कासगंज से भी आया है। दरअसल, यहां पर एक व्यक्ति करा मन अपने पत्नी से भर गया तो वह अपनी सास के साथ दिल लगा लिया। जिसके बाद दोनों के बीच आए दिन संबंध बनने लगे। इतना ही नहीं बवाल तब मच गया जब इन दोनों की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी।

मिली जानकारी के अनुसार, पत्नी अपने पति के कारनामे की जैसे ही भनक लगी तो वह उसका विरोध करने लगी। जिसको लेकर अक्सर दोनों के बीच मारपीट होती थी। इतना ही नहीं ससुर नारायण

सिंह को किसी तरह से ये तस्वीरें हाथ लग गईं जिसे उन्होंने पुलिस को सौंपे दिया है। उसको लेकर भी दामाद और सास ससुर को भी पीटते थे। इन सबके बीच शिवानी तनाव में रहती थी और एक दिन वह अपनी ससुराल में मृत पाई गई। उसकी हत्या हुई या आत्महत्या की, अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। मायके वालों को जब खबर लगी तो वह शिवानी के ससुराल सिढ़पुरा क्षेत्र के नगला पारसी पहुंचे। बेटी की लाश चारपाई पर पड़ी थी और दामाद प्रमोद फरार था।

गौरतलब है कि शिवानी और प्रमोद की शादी 2018 में ही हो गई थी। 24 वर्षीय शिवानी गंजडुंडवारा क्षेत्र के पालिया गांव की रहने वाली थी। प्रमोद दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता है। छोटी बेटी शिवानी की शादी धूमधाम से की थी। करीब 6 महीने बाद ही उसकी पत्नी प्रेमवती के दामाद के साथ अवैध संबंध हो गए। वहीं, अब पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि रविवार रात साढ़े 8 बजे घटना की सूचना ग्रामीणों ने दी थी। मौके पर जाकर देखा तो महिला का शव चारपाई पर पड़ा था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चलेगा। ससुराल के लोग फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई की जाएगी।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)

महिला विश्व कप : पाकिस्तान के खिलाफ जीत के प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा ऑस्ट्रेलिया

कोलंबो **(एजेंसी)**। अपने अभियान की शानदार शुरुआत करने वाला ऑस्ट्रेलिया बुधवार को यहां आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा। पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट में लय हासिल करने के लिए जूझ रही है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया का शानदार प्रदर्शन अन्य टीम के प्रदर्शन से बिल्कुल अलग रहा है।

एलिसा हीली की अगुवाई वाली टीम अब तक टूर्नामेंट में 300 से अधिक का स्कोर बनाने वाली एकमात्र टीम रही है और पिछले दो मैच में बांग्लादेश और भारत के खिलाफ कमजोर दिखे पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने 300 से अधिक का स्कोर खड़ा करने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 89 रन की आसान जीत दर्ज की थी।

टीम की नजरें रिकॉर्ड में सुधार करने वाले आठवें विश्व कप खिताब पर टिकी हैं। हालांकि सलामी बल्लेबाज एलिसा हीली, बेथ मूनी और

एनाबेल सदरलैंड जैसी बल्लेबाज लड़खड़ा रही हैं लेकिन एश्ले गार्डनर ने इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में शानदार शतक जड़कर अंत में मुकाबला एकतरफा बना दिया। एनाबेल सदरलैंड की तेज गेंदबाजी और सोफी मोलिन्यु की स्पिन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी विभाग में अच्छा प्रदर्शन किया है और इंग्लैंड, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका जैसी कड़ी टीमों से मुकाबला करने से पहले टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपनी रणनीति को और मजबूत करने की कोशिश करेगी।

भारत के खिलाफ तीन मैच की एकदिवसीय श्रृंखला ने ऑस्ट्रेलिया को उपमहाद्वीप के मैदानों पर कड़ी मेहनत के लिए अच्छी तरह तैयार किया है और पाकिस्तान के उसे परेशान करने की संभावना नहीं है। बांग्लादेश और भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान आठ टीम के टूर्नामेंट में अभी अंतिम स्थान पर है। हालांकि शनिवार को आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ रद्द हुआ मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए निराशाजनक रहा क्योंकि इसने टीम से दो अंक अर्जित करने और तालिका में शीर्ष पर पहुंचने का मौका छीन लिया। फातिमा सना की अगुआई वाली पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश (सात विकेट से हार) और भारत (88 रन से हार) के खिलाफ मैच में खेल के सभी विभागों में कमजोर साबित हुई। टीम की बल्लेबाजी में गहराई की कमी और मध्यक्रम में अच्छे बल्लेबाजों की अनुपस्थिति के कारण पाकिस्तान टूर्नामेंट में अब तक दो मैच में 200 रन के आंकड़े को भी नहीं छू पाया है।

मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला : 24, 634 करोड़ की रेल परियोजनाएं, 4 राज्यों में बदलेगी तस्वीर

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। रेल अवसंरचना को बढ़ाने और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में फैली चार मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की एक विज्ञप्ति के अनुसार, इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारतीय रेलवे नेटवर्क का लगभग 894 किलोमीटर तक विस्तार करना है और इनके 2030-31 तक पूरा होने की उम्मीद है।

स्वीकृत परियोजनाओं में महाराष्ट्र में वर्धा-भुसावल खंड (314 किमी) पर तीसरी और चौथी लाइनों का निर्माण, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को कवर करते हुए गोंदिया-डोंगरगढ़ खंड (84 किमी) पर चौथी लाइन, गुजरात और मध्य प्रदेश को कवर करते हुए वडोदरा-रतलाम खंड (259 किमी) पर तीसरी और चौथी लाइन, और मध्य प्रदेश में इटारसी-भोपाल-बीना खंड (237 किमी) पर चौथी लाइन का निर्माण शामिल है। ये परियोजनाएं कुल मिलाकर 18 जिलों को सेवा प्रदान करेंगी और 85.84 लाख से अधिक की संयुक्त आबादी वाले लगभग 3, 633 गांवों को बेहतर रेल संपर्क प्रदान करेंगी, जिसमें दो आकांक्षी जिले - मध्य प्रदेश में विदिशा और छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव शामिल हैं।

ये मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ लाइन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि, भीड़भाड़ कम करने और भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता एवं सेवा विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ये परियोजनाएँ प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप भी हैं और इनसे सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों में आर्थिक विकास और रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत नियोजित, इन परियोजनाओं का उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श के माध्यम से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाना और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना है। उन्नत रेल लाइनें यात्रियों और माल ढुलाई दोनों के लिए निर्बाध परिवहन प्रदान करेंगी, जिससे सांची, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भीमबेटका रॉक शेल्टर, हज़ारा फॉल्स और नवेगाँव राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों तक बेहतर पहुँच संभव होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मार्ग कोयला, सीमेंट, कंटेनर, फ्लाई ऐश, खाद्यान्न और इस्पात सहित आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विस्तारित क्षमता से प्रति वर्ष 78 मिलियन टन (एमटीपीए) अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।

पीएम-कुसुम योजना को मिलेगा दूसरा जीवनदान! सरकार फिर बढ़ाएगी समय-सीमा, लक्ष्य अभी भी दूर

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। सरकार पीएम-कुसुम योजना की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा सकती है क्योंकि इस पहल के दो प्रमुख घटक अपने लक्ष्य का 50 प्रतिशत भी हासिल नहीं कर पाए हैं। आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना 2019 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य 2022 तक 30, 800 मेगावाट की सौर क्षमता जोड़ना था।

इसमें कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए सेवा शुल्क सहित कुल 34, 422 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल थी। केंद्र ने बाद में पीएम-कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया क्योंकि वैश्विक महामारी के कारण इसका कार्यान्वयन काफी प्रभावित हुआ था। लक्ष्य को भी संशोधित कर 34, 800 मेगावाट कर दिया गया था। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पीएम कुसुम के कार्यान्वयन की समय-सीमा को और बढ़ाए जाने के आसार हैं। यह इस योजना का दूसरा विस्तार होगा।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस महत्वाकांक्षी योजना के किसी भी घटक ने 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल नहीं किया है। यद्यपि योजना का घटक 'ख' (जो मार्च 2026 को समाप्त होगा) नौ सितंबर तक लक्ष्य का 71 प्रतिशत पूरा करने में सक्षम रहा है। घटक 'क' ने केवल 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। घटक 'ग'- व्यक्तिगत पंप का सौरीकरण (आईपीएस) एवं घटक 'ग' - फीडर स्तरीय सौरीकरण (एफएलएस) ने क्रमशः 16.5 प्रतिशत और 25.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अनुसार, घटक 'क' छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करके 10, 000 मेगावाट सौर क्षमता की स्थापना से जुड़ा है। घटक 'ख' 14 लाख ऑफ-ग्रिड एकल सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना और घटक 'ग' 35 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण से संबद्ध है। घटक 'क' के तहत 650.49 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई है। दूसरी ओरघटक 'ख' के तहत 12.72 लाख से अधिक ऑफ-ग्रिड सौर पंप स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 9.03 लाख स्थापित किए जा चुके हैं।

शतक लगाया, फिर भिड़ गए!, पृथ्वी शॉ की वापसी के साथ मैदान पर मचा हंगामा

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। लंबे समय से फॉर्म और चयन दोनों से जूझ रहे पृथ्वी शॉ ने आखिरकार धमाकेदार वापसी का ऐलान किया। महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए उन्होंने अपनी पूर्व टीम मुंबई के खिलाफ अभ्यास मैच में शानदार शतक ठोका। लेकिन पारी खत्म होते ही मैदान पर एक अप्रत्याशित घटना हुई, शॉ की मुशीर खान से गर्मागर्मी हो गई, जिसे अंपायरों को रोकना पड़ा। मंगलवार को हुए अभ्यास मैच में शॉ ने महाराष्ट्र के लिए मुंबई के खिलाफ सिर्फ़ 220 गेंदों में 181 रन बनाए। इस पारी में 21 चौके और तीन छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाज़ी ने न सिर्फ़ विरोधी गेंदबाजों को परेशान किया बल्कि चयनकर्ताओं को भी यह याद दिलाया कि वह अब भी घरेलू क्रिकेट में बड़ा नाम हैं। आउट होने के बाद शॉ और मुंबई के युवा ऑलराउंडर मुशीर खान के बीच बहस हो गई। मुशीर ने विकेट गिरने के बाद जोरदार सेलिब्रेशन किया, जिससे शॉ भड़क गए। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और स्थिति बिगड़ने लगी, तब जाकर अंपायर और साथी खिलाड़ी बीच-बचाव करने पहुंचे। बाद में मामला शांत कराया गया।

27 वर्षीय शॉ का करियर पिछले कुछ वर्षों में विवादों और अनुशासनहीनता के कारण प्रभावित हुआ। आईपीएल 2025 की नीलामी में कोई टीम उन्हें नहीं खरीद पाई। अब महाराष्ट्र ने उन्हें दोबारा मौका दिया है। शॉ अब पहले से अधिक फिट और केंद्रित नजर आ रहे हैं, और इस प्रदर्शन ने उनके आत्मविश्वास को नई उड़ान दी है।

मिताली राज और रवि कल्पना के नाम पर होंगे विजाग स्टेडियम के स्टैंड

विशाखापट्टनम **(एजेंसी)**। भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज और विकेटकीपर बल्लेबाज रवि कल्पना के नाम पर विशाखापट्टनम क्रिकेट स्टेडियम के स्टैंड रखे जाएंगे। 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप का भारत का मैच होने से पहले इस स्टैंड का उद्घाटन होगा। अगस्त में ब्रेकिंग द बाउंड्रीज चैट के दौरान भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्टर नारा लोकेश को सुझाव दिया था जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

एसीए ने अपने बयान में कहा, 'मिताली राज और रवि कल्पना को समर्पित एसीए का यह सम्मान इस बात को दर्शाता है कि भारतीय महिला क्रिकेट को नई पहचान देने वाली इन अग्रदूतों के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता है। उन्होंने आने वाली पीढ़ी को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी है।' मंत्री लोकेश ने कहा, 'स्मृति मंधाना का विचार जनता की व्यापक भावना को दर्शाता है। उस सुझाव को तुरंत अमल में लाना हमारे सामूहिक संकल्प को दिखाता है। लैंगिक समानता के प्रति और महिला क्रिकेट की अग्रदूतों को सम्मान देने के प्रति।' मिताली महिला क्रिकेट की दिग्गजों में से एक है जिनके नाम महिला वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 232 वनडे मैचों में 50.68 की औसत के साथ 7805 रन बनाए हैं जिसमें 7 शतक शामिल रहे हैं। भारत के लिए खेले 89 टी20 मैचो में उन्होंने 17 अर्धशतकों के साथ 2364 रन बनाए हैं और इस दौरान उनकी औसत 37.52 की रही है। 12 टेस्ट मैचों में मिताली ने लगभग 44 की औसत के साथ 699 रन बनाए हैं और इस दौरान 214 उनका बेस्ट स्कोर रहा है जो इस प्रारूप में किसी भारतीय का सर्वोच्च स्कोर भी है। 2022 में उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था और इस तरह उनके 23 साल के लंबे करियर का अंत हुआ था। 2015 और 2016 के बीच कल्पना ने 7 वनडे मैच खेले और उनके भारतीय टीम तक का सफर तय करने से अरुंधति रेड्डी, एस मेघना और श्री चरणी जैसी अन्य क्रिकेटरों को भी इस क्षेत्र से भारतीय टीम तक जाने की प्रेरणा मिली।

भारत-पाकिस्तान मुकाबले में विवादित रन आउट पर एमसीसी ने सुनाया फैसला

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। कोलंबो में महिला विश्व कप 2025 के भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान एक रन आउट को लेकर विवाद हुआ। पाकिस्तान की बल्लेबाज मुनीबा अली को आउट किया गया, जिससे मैच में बड़ी हलचल मची।

मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने इस विवादित रन आउट पर अपना फैसला सुना दिया है।

मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने सोमवार को स्पष्ट किया कि मुनीबा अली को रन आउट देना पूरी तरह सही था। घटना पाकिस्तान की पारी के चौथे ओवर में हुई, जब दीप्ति शर्मा की गेंद मुनीबा के पैड पर लगी और भारत ने एलबीडब्ल्यू की अपील की। अंपायर ने पहले 'नॉट आउट' दिया, लेकिन दीप्ति ने गेंद तेजी से स्टंप्स की ओर फेंक दी, जबकि मुनीबा क्रीज से बाहर थीं। तीसरे अंपायर ने रिव्यू लिया और मुनीबा को आउट करार दिया।

एमसीसी ने कहा, 'एमसीसी ने बताया कि गेंद तब भी खेल में थी, इसलिए रन आउट देना सही था। 'एलबीडब्ल्यू अपील के बावजूद गेंद डेड नहीं हुई थी। मुनीबा क्रीज़ में नहीं थी और बल्ला हवा में उठा रखा था, इसलिए उनका आउट होना नियमों के अनुसार सही था।' एमसीसी ने यह भी स्पष्ट किया कि 'बाउंसिंग बैट नियम' केवल दौड़ते समय लागू होता है, और मुनीबा इस स्थिति में नहीं थीं।

त्योहारी सीजन में ग्राहकों का भरोसा लौटा नवरात्रि में गाड़ियों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री इस साल नौ दिन की नवरात्र अवधि में सालाना आधार पर 35 प्रतिशत बढ़ी जिससे पिछले महीने कुल पंजीकरण में छह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वाहन डीलर के संगठन फाडा ने मंगलवार को यह जानकारी दी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के अनुसार, सितंबर महीने के पहले 21 दिन में बिक्री धीमी रही और 22 सितंबर को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दरें लागू होने के बाद इसमें तेजी आई। नवरात्रि के दौरान यात्री वाहन की कुल खुदरा बिक्री 2, 17, 744 इकाई रही जबकि पिछले वर्ष नवरात्रि अवधि में यह 1, 61, 443 इकाई रही थी।

वाहन डीलर के संगठन के अनुसार, इस उच्च बिक्री के कारण सितंबर में यात्री वाहन खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 2, 82, 945 इकाई से छह प्रतिशत बढ़कर 2, 99, 369 इकाई हो गई। 22 सितंबर के बाद नई जीएसटी दर लागू होने के बाद कीमतों में कटौती की उम्मीद कर रहे ग्राहकों ने महीने के पहले हिस्से में खरीदारी नहीं की। फाडा के उपाध्यक्ष साई गिरिधर ने बयान में कहा, " देश के मोटर वाहन खुदरा उद्योग के लिए सितंबर 2025 एक असाधारण रूप से अनूठा महीना था। पहले तीन सप्ताह काफी हद तक शांत रहे क्योंकि ग्राहक जीएसटी 2.0 सुधारों की प्रत्याशा में पीछे हट गए। हालांकि, अंतिम सप्ताह में स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई क्योंकि नवरात्रि उत्सव कम जीएसटी दरों के कार्यान्वयन के साथ मेल खाता था जिससे ग्राहक भावना में सुधार हुआ और अधिकतर वाहन श्रेणियों की बिक्री में तेजी आई।"

उन्होंने कहा कि परिणामस्वरूप माह का अंत कुल मिलाकर पांच प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ हुआ जिसमें तिपहिया और निर्माण उपकरण को छोड़कर सभी खंडों में सकारात्मक गति देखी गई। फाडा के अनुसार, सितंबर के अंतिम दिन में बनी गति दीपावली तक जारी रहेगी जिससे त्यौहार की इस 42 दिन की अवधि के सकारात्मक रुख के साथ खत्म होने की उम्मीद है। आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री 12, 87, 735 इकाई रही जो सितंबर 2024 में 12, 08, 996 इकाइयों के मुकाबले सात प्रतिशत अधिक है।

महाराष्ट्र शासन
इलाखा शहर विभाग, (सा.बां.)

ई-निविदा सुचना क्र. ५० सन २०२५-२०२६

कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई (दुरध्वनी क्रमांक-२२०१६९७५ / २२०१६९७७) महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे योग्य वर्गातील नोंदणीकृत कंत्राटदाराकडून खालील कामाकरीता ब-१ नमुन्यातील निविदा ई- निविदा प्रणालीव्दारे (ऑनलाईन) मागवित आहेत. निविदा स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई यांनी राखून ठेवला आहे.

अ.क्र.	कामाचे नाव	अंदाजित रक्कम रू. लक्ष
१.	चर्चगेट मुंबई येथील सागर इमारत रुम नं. ४ येथे दरवाजा, खिडक्या, स्टोरेज युनिट, प्रसाधनगृह, किचन ओटा, ट्रॉली, प्लास्टर, रंगकाम करणे.	९.५७
२.	चर्चगेट मुंबई येथील आसावरी इमारत रुम नं. ३०३ येथे दुरुस्ती करणे.	१२.४१
३.	नविन विधान भवन मुंबई येथील टॉवर इमारत येथील सेंट्रल हॉल येथे दरवाजा, खिडक्या, सिटींग अरेंजमेंट, सीट, हँडल, असेंबली इ. फर्निचर चे काम करणे.	२२.०६
४.	बेलहेवन मुंबई येथील फ्लॅट नं. २३ येथे टाईल्स, पॉलीमर मोर्टर, दरवाजा, खिडक्या, प्रसाधनगृह, रंगकाम, प्लास्टर व दुरुस्ती करणे.	१६.४५
५.	बेलहेवन मुंबई येथील फ्लॅट नं. ९ येथे किचन ओटा, कॅबीन, प्लॅबिंग वर्क, फ्लोरींग, दरवाजा, खिडक्या, बालकनी, पॉलीमर मार्टर, प्लास्टर, रंगकाम, दुरुस्ती करणे.	१२.६८
६.	इंस्टीट्युट ऑफ सायन्स इमारत मुंबई येथील १ मजल्यावरील एच बी एस यु डॉ. होमी भाग ग्रंथालय येथील सेमिनार हॉल व लायब्ररी चे नुतनीकरण करणे.	२०.९०
७.	इंस्टीट्युट ऑफ सायन्स इमारत मुंबई येथील २ मजल्यावरील रुम नं. १२ येथे एच बी एस यु शोध रीसर्च डेवलेपमेंट सेल सेंट्रल इंस्ट्रुमेंटेशन फॅसिलीटी सेंटर येथे रंगकाम व दुरुस्ती करणे.	११.०१
८.	मलबार हील मुंबई येथील शासकीय बंगलो सातपुडा, शिवनेरी, पर्णकुटी, ज्ञानेश्वरी, रॉयल स्टोन, चित्रकुट, जेनवन, मुक्तागीरी येथे वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करणे.	६९.१२
९.	मंत्रालय मुंबई येथील मुख्य इमारत ५ मजल्यावरील सी एम पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफिस कॅबीनची नुतनीकरण करणे.	११.०९
१०.	शहिद भगतसिंग रोड मुंबई येथील टॉउन हॉल इमारत येथे १ मजल्यावरील डायरेक्टर लायब्ररी ऑफिस येथे अंतर्गत प्लास्टर, दरवाजा, खिडक्या, रंगकाम व दुरूस्ती करणे.	१८.६७
११.	इंस्टीट्युट ऑफ सायन्स कॉलेज इमारत मुंबई येथील मॅथमॅटिक इमारत येथील तळमजला ते २ मजल्यावरील पॅसेज, जिना व प्रसाधनगृह येथे प्लास्टर रंगकाम व दुरूस्ती करणे.	१६.६७
१२.	नविन विधानभवन मुंबई येथील डोम व टॉवर इमारत तळमजला ते ३ मजल्यावरील चेंबर पार्टीशन, दरवाजा, खिडक्या, इ. नुतनीकरण व दुरुस्ती करणे.	२२.५५
१३.	चर्चगेट मुंबई येथील विभावरी १०३ येथे नुतनीकरण व दुरुस्ती करणे.	१२.७५
१४.	पोलीस मुख्यालय आवार मुंबई येथील विधानभवन कर्मचारी सर्वंट क्वार्टर्स रुम नं. ४ व ६ येथे प्रसाधनगृह, टाईल्स, ओटा, रंगकाम, नुतनीकरण व दुरूस्ती करणे.	१४.३७
१५.	उच्च न्यायालय विस्तार इमारत मुंबई येथील सिव्हील डिपार्टमेंट साईड मंगलोरी छताची दुरूस्ती करणे.	१६.९२
१६.	पी. डीमेलो रोड मुंबई येथील कमांडो व कॉस्टेबल २ मजल्यावरील रूम, प्रसाधनगृह, पॉलिमर मोर्टर, फ्लोरींग,डॅडो, किचन इ. रंगकाम, दुरूस्ती व नुतनीकरण करणे.	
१७.	जुने जकात घर मुंबई येथील डी. डी. इमारत आवारातील वॉटर सप्लाय व रेन वॉटर पाईप लाईन दुरूस्ती करणे.	९.३८
१८.	एक्साईज कार्यालय मुंबई येथील तळमजल्यावरील अंतर्गत प्लास्टर, फ्लोरींग, रंगकाम, दरवाजा, खिडक्या, प्रसाधनगृह दुरुस्ती चे काम करणे.	१३.८४
१९.	सिटी सिव्हील कोर्ट आवार मुंबई येथील तळमजल्यावरील बॅरेक व कुलर प्लॅटफॉर्म विभाग येथे शेड दुरुस्ती चे काम करणे.	१०.८२
२०.	जुने जकात घर मुंबई येथील कलेक्टर ऑफिस मागील बाजूस ५ कोट फायबर रेनफोर्स रंगकाम, छज्जा, मंगलोरी छताची दुरूस्ती व नुतनीकरण करणे.	१८.७५

ई-निविदा उपलब्ध कालावधी दि. ८.१०.२०२५ ते दि. १५.१०.२०२५ पर्यंत. ई-निविदा उघडणे दि. १६.१०.२०२५ रोजी दुपारी ३.०० वाजता निविदा सुचने मध्ये काही बदल/सुधारणा करावयाची असल्याचे शुध्दीपत्रक वृत्तपत्रामध्ये प्रसिध्द करण्यात येणार नाही. त्याबत सर्व बदल ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेमध्ये प्रसिध्द केले जाईल. खालील संकेतस्थळावरुन ई-निविदाची सर्व माहीती उपलब्ध आहे.
१) www.mahapwd.com
२) http://mahatenders.gov.in

जा.क्रं. इशवि/निलि/ १०१८०
कार्यकारी अभियंता
इलाखा शहर विभाग, मुंबई यांचे कार्यालय,
सार्वजनिक बांधकाम विभाग,
२ रा मजला, बांधकाम भवन,
२५ मर्झबान रोड, फोर्ट,
मुंबई- ४०० ००१.
Email: presidency.ee@mahapwd.gov.in
दिनांक : ३०.०९.२०२५

DGIPR/2025-26/2975

(व्ही. ए. पाटसकर)
कार्यकारी अभियंता,
इलाखा शहर विभाग, मुंबई.

बिग बॉस 19 मालती चाहर ने बिग बॉस में आते ही मचाया बवाल

मुंबई। भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर हाल ही में सलमान खान के शो, बिग बॉस 19 में नज़र आए। हालाँकि, शो में उनकी उपस्थिति किसी प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं, बल्कि अपनी बहन मालती चाहर को सीज़न की दूसरी वाइल्डकार्ड प्रतिभागी के रूप में पेश करने के लिए थी। मालती ने रविवार को घर में प्रवेश किया और तब से ही घरवाले इस बात को लेकर कयास लगा रहे हैं कि वह किस ग्रुप में शामिल हो सकती हैं। हालाँकि, एक प्रतिभागी जो उनके प्रवेश के बाद विशेष रूप से असहज लग रही हैं, वह हैं तान्या मित्तल। सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस रियलिटी शो में प्रवेश करने से कुछ मिनट पहले, इस अभिनेत्री-लेखिका ने इंडिया टुडे से विशेष बातचीत की और अपनी रणनीतियों पर चर्चा की।

दिलचस्प बात यह है कि यह पहला सीज़न है जिसे मालती ने देखा है, लेकिन यह उन्हें अपना प्रशंसक बनाने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा, 'मैंने 'बिग बॉस' का सिर्फ़ यही सीज़न देखा है और मुझे यह बहुत पसंद आया। इसलिए जब मुझे वाइल्डकार्ड के तौर पर शो में आने का प्रस्ताव मिला, तो मैंने तुरंत हाँ कर दिया।'

कई लोग जो सीज़न के बीच में शो में शामिल होने को लेकर चिंतित रहते हैं, उनके विपरीत, मालती को इस बात की साफ़ समझ थी कि वह क्या करने जा रही हैं। उन्होंने बताया कि छह हफ़्तों के बाद घर में प्रवेश करना उनके लिए

फ़ायदे और नुकसान दोनों साबित होगा। हर प्रतियोगी और उनके खेल को जानना उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि घर में और दर्शकों के दिलों में जगह बनाने के लिए उनसे मुकाबला करना भी एक चुनौती होगी।

फ़िलहाल घर दो ग्रुपों में बँटा हुआ है, लेकिन मालती ने स्वीकार किया कि वह अभी किसी एक पक्ष को चुनने के मूड में नहीं हैं। 'मैं किसी टीम में शामिल नहीं होना चाहती। लेकिन मैं अपने लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहती हूँ। मैं कोई तीसरा ग्रुप नहीं बनाना चाहती। मैं सबके साथ बातचीत करूँगी और फिर तय करूँगी कि क्या करना है। हालाँकि, मैं अमाल और उनकी टीम को ज़रूर बेहतर तरीके से जानना चाहूँगी।

अपनी रणनीति के बारे में बात करते हुए, मालती चाहर ने कहा कि वह इसे पूरी तरह से गुप्त रखना चाहती हैं। उन्होंने हँसते हुए कहा, 'मैं यह किसी को नहीं बताऊँगी। यह एक निजी राज़ है।' अभिनेत्री ने यह भी कहा कि खेल के अलावा, वह हर हफ़्ते होस्ट सलमान खान से बातचीत करने और उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए उत्सुक हैं।

हालाँकि वह क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन के रूप में ज़्यादा जानी जाती हैं, मालती ने कहा कि वह अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं। मॉडल ने यह भी कहा कि वह अपने परिवार के किसी दबाव या अपने भाई की छवि बचाने की ज़िम्मेदारी के बिना, अपनी पहचान के साथ 'बिग बॉस' में कदम रख रही हैं। मालती ने कहा 'वे बहुत खुश हैं कि मैं 'बिग बॉस' में हूँ। मुझे उनसे कोई 'क्या करना है और क्या नहीं' वाली बात नहीं मिल रही है। दीपक मुझे बस खेल खेलने के तरीके के बारे में कुछ सलाह दे रहे हैं। बाकी, वह खुश हैं कि मैं वहाँ जा रही हूँ,' उन्होंने बताया और बताया कि भारतीय क्रिकेटर ने भी पहली बार 'बिग बॉस' देखना शुरू किया, सिर्फ़ उनका समर्थन करने के लिए।

सिडको शहर बनाए, शहर बसाए. | सत्यमेव जयते भारत सरकार | महाराष्ट्र शासन | Navi Mumbai International Airport

राष्ट्रीय विकास के एक नए युग का शुभारंभ, आकांक्षाओं की पूर्ति का उत्सव

उद्घाटन

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

महा-मुंबई के लिए ₹ १९,६५० करोड़ की लागत से निर्मित एक आधुनिक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा

DGIPR/2025-26/2982B

माननीय प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी

इनके करकमलों द्वारा

- दिनांक: बुधवार ०८ अक्टूबर २०२५
- दोपहर: ३:०० बजे
- स्थल: नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रकल्प स्थल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र

- विकास उत्प्रेरक : एनएमआईए से एमएमआर में राजस्व, रोज़गार, रियल एस्टेट और व्यावसायिक अवसरों में होगी बढ़ोत्तरी।
- मल्टी-मॉडल हब : भारत का पहला वास्तविक मल्टी-मॉडल एविएशन हब, जो लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स, आतिथ्य और पर्यटन में वृद्धि को बढ़ावा देगा।
- वार्षिक यात्री संचालन क्षमता २० मिलियन (चरण-१) और ९० मिलियन (अंतिम चरण)
- वार्षिक कार्गो संचालन क्षमता ०.८ मिलियन मीट्रिक टन (चरण- १) और ३.२५ मिलियन मीट्रिक टन (अंतिम चरण)
- महाराष्ट्र और भारत की स्थानीय और क्षेत्रीय सांस्कृतिक विरासत के जीवंत अनुभव को प्रदान करती डिजिटल और भौतिक कला प्रदर्शनी
- 'कमल' से प्रेरित, यात्री टर्मिनल भवन की रचना पारंपरिक भारतीय परिवेश और भविष्य की भव्यता और कार्यक्षमता का एक अद्वितीय मिश्रण है
- दो स्वतंत्र रनवे के साथ प्रत्येक रनवे के लिए दो समानांतर टैक्सीवे
- कुल क्षेत्रफल - ११६० हेक्टेयर
- भारत का पहला वास्तविक मल्टी-मॉडल हवाई अड्डा, जो एक्सप्रेस वे, मेट्रो, उपनगरीय रेलवे और जल टैक्सियों से निर्बाध रूप से जुड़ा होगा।
- अनुकूलनयोग्य और भविष्यकेंद्रित तैयार तकनीकों का एकीकरण, जिससे खुदरा खरीदारी, खाद्य एवं पेय, ड्युटी फ्री खरीदारी, सामान प्रबंधन और लाउंज चेक-इन के लिए डिजिटल सेवाओं की आसान उपलब्धता

DD NEWS डी. डी. न्यूज पर सीधा प्रसारण